वर्ष : 33 ▸ अंक : 317 ▸ पृष्ठ : 8 ▸ मुंबई, रविवार, 2 फरवरी 2025 ▸ RNI: MAHHIN/49994/91 ▸ मूल्य : 3 रुपए ▸ epaper.dobajedopahar.com ▸ संपादक : अरुण लाल

DBD दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

देश को खिलौना हब बनाया जाएगा, अभी 64% आयात चीन से

आम बजट 2025

पीएम मोदी का मिडिल क्लास वाला बजट

मिडिल क्लास की पौ 'बारह'

₹12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री

पहली बार 50 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश

मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट पुरानी सोच से अलग है । आउट ऑफ बॉक्स से भरपूर है । प्रधानमंत्री के इस बजट को समझने के लिए, देखने के लिए, भांपने के लिए नए नजरिए की जरूरत है, क्योंकि मोदी का बजट परंपरागत सोच वाले बजट से एकदम अलग है, सरप्राइज से भरपूर है । बजट में रोटी-कपड़ा और मकान का पूरा ख्याल है, तो प्रधानमंत्री ने देश के मिडिल क्लास को भी उम्मीदों से ज्यादा दिया है । यही है मोदी की वर्किंग स्टाइल, इनकम टैक्स में छूट दी तो वो भी छप्पर फाड़ के । मोदी का मिडिल क्लास वाला बजट ऐसा है कि उनके आलोचक भी इस मुद्दे पर असहमत नहीं हो सकते हैं । दरअसल बजट 2025-26 का फोकस GYAN पर है । यह GYAN भारत के उन लोगों का समूह है जो बीजेपी के बड़े वोटर में शामिल हैं । GYAN मतलब G-गरीब, Y-युवा, A-अन्नदाता यानी कि किसान और N-नारी । मोदी सरकार ने इस बजट में इन चार कैटेगरी के लोगों के लिए खजाने का पिटारा खोल दिया गया है । इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बार नौकरीपेशा लोगों को भी बमबम कर दिया है । मध्य वर्ग की हमेशा शिकायत कमाई पर करों में छूट से रहती थी । इस बजट में सरकार ने नौकरी कर रहे लोगों को एकमुश्त बंपर राहत दी है ।

एजेंसी । नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट अनुमान 50,65,345 करोड़ रुपये है, जिसमें कुल पूंजीगत व्यय 11,21,090 करोड़ रुपये है। इसमें राज्यों को 25,01,284 करोड़ रुपये मिलेंगे। सरकार ने बताया कि बजट में कुल राजस्व प्राप्ति 34,20,409 करोड़ रुपये है। वहीं पूंजीगत प्राप्तियां 16,44,936 करोड़ रुपये हैं। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के लिए भी बजट तय किया है।

बजट में मध्यवर्ग को बड़ी सौगात

12 लाख रुपये तक की सालाना आय को आगामी वर्ष के लिए कर मुक्त करने की भी घोषणा की। आयकर से जुड़ी अन्य दरों (स्लैब) में भी परिवर्तन कर दिया गया है। 24 लाख से अधिक की सालाना आय वाले लोगों पर ही 30 प्रतिशत की दर से उच्च आयकर लगेगा, जो अभी तक 15 लाख से अधिक की आय पर लागू होता है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल 50.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है, जो बीते वर्ष जुलाई में पेश किए गए आम बजट की तुलना में 2.44 लाख करोड़ अधिक है।

बजट में मध्यवर्ग को बड़ी सौगात

12 लाख रुपये तक की सालाना आय को आगामी वर्ष के लिए कर मुक्त करने की भी घोषणा की। आयकर से जुड़ी अन्य दरों (स्लैब) में भी परिवर्तन कर दिया गया है। 24 लाख से अधिक की सालाना आय वाले लोगों पर ही 30 प्रतिशत की दर से उच्च आयकर लगेगा, जो अभी तक 15 लाख से अधिक की आय पर लागू होता है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल 50.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है।

खेती बनेगी अर्थव्यवस्था का पहला इंजन

बजट में सबसे ज्यादा जोर कृषि सेक्टर पर दिया गया है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए इसे अर्थव्यवस्था का प्रथम इंजन बताया गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की विकास यात्रा के लिए पूरे कृषि बजट में कई दूरगामी नीतिगत मामलों की तस्वीर पेश की है। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। पीएम धन-धान्य कृषि योजना से 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा, खासकर उन जिलों में जहां कृषि उत्पादकता कम है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपये तक के लोन की सुविधा मिलेगी। तुअर, उड़द और मसूर दाल के लिए छह साल का मिशन चलेगा, जबकि कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए पांच साल की कार्ययोजना के तहत प्रोडक्शन और मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। श्रीअन्न और फलों के लिए राज्यों के सहयोग से नई योजनाएं शुरू होंगी। समुद्री उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे ये सस्ते होंगे और अंडमान-निकोबार में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा और मिथिलांचल में कोसी नहर परियोजना से 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा मिलेगा। असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा। सहकारी क्षेत्र में कर्ज सुविधा के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता दी जाएगी, और पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाएं ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएंगी।

देश के युवाओं पर मेहरबान हुई वित्त मंत्री

सरकार ने बजट 2025 में युवाओं के लिए कई सारे ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने इस बजट में एजुकेशन, स्टार्टअप और रोजगार को काफी प्राथमिकता दी है। स्टार्टअप के प्रोत्साहन के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए की लागत से 3 एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 वर्षों में 75 हजार नई सीटें जोड़ी जाएंगी, जबकि देश के 23 IIT में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में भी 10 हजार नई सीटें जोड़ी जाएंगी। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10 हजार नई फेलोशिप प्रदान की जाएंगी, जिससे उच्च शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा। ज्ञान भारत मिशन के तहत 1 करोड़ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। पटना IIT में होस्टल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। 'मेक इन इंडिया' और 'मेक फॉर वर्ल्ड' अभियानों को भी मजबूती दी जाएगी। कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, और सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।

व्यापारियों और उद्यमियों के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में व्यापार जगत, MSME सेक्टर और छोटे उद्यमियों को समर्थन देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. इन घोषणाओं का उद्देश्य व्यापार को आसान बनाना, फंडिंग बढ़ाना और रोजगार के नए अवसरों को उत्पन्न करना है. एसएमई और बड़े उद्योगों के लिए विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है, जबकि निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमश: 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण गारंटी शुल्क घटाकर 1% कर दिया गया है। निर्यातक MSME को 20 करोड़ रुपये तक का सावधि कर्ज मिलेगा और निर्यात संवर्धन मिशन की स्थापना की जाएगी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण उपलब्ध होगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर-2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने के लिए राष्ट्रीय योजना बनाई जाएगी, जबकि नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे और पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी करने का लक्ष्य है। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत लोन लिमिट बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दी गई है। KYC प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2025 में संशोधित केंद्रीय KYC रजिस्ट्री शुरू होगी। जन विश्वास बिल 2.0 के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध के दायरे से हटाया जाएगा।

नौकरीपेशा

नौकरीपेशा के लिए 75 हजार स्टैंडर्ड डिक्शन के साथ टैक्स छूट 12.75 लाख हुई। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 करोड़ गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा योजना मिलेगी। गिग वर्कर्स का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इनकम टैक्स बिल में वर्तमान कानून की तुलना में लगभग 50% कम टेक्सट होगा। इसे समझना आसान होगा, जिससे मुकदमेबाजी में कमी आएगी।

महिलाएं

SC -ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष टर्म लोन योजना आएगी।
पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।
महिलाओं को 5 साल के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन, 5 लाख महिलाओं को फायदा।
महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मेंटरशिप प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जाए।
महिला उद्यम को बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की सुविधा भी दी जाएगी।
सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की शुरुआत होगी।

बुजुर्ग

सीनियर सिटिजंस के लिए टैक्स छूट दोगुनी, 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए।
कैंसर, दुर्लभ और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री।
देश में 200 डे-केयर कैंसर सेंटर बनेंगे।
मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर।

महाराष्ट्र को बजट में क्या मिला?

- मुंबई मेट्रो : 1255.06 करोड़
- पुणे मेट्रो : 699.13 करोड़
- एमयूटीपी : 511.48 करोड़
- एमएमआर के लिए एकीकृत और हरित यात्री सुविधाएं : 792.35 करोड़
- मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे : 4004.31 करोड़
- समावेशी विकास के लिए आर्थिक क्लस्टर : 1094.58 करोड़
- महाराष्ट्र ग्रामीण सुधार परियोजना : 683.51 करोड़
- महाराष्ट्र एग्रीबिजनेस नेटवर्क : 596.57 करोड़
- नागानदी सुधार परियोजना : 295.64 करोड़
- मुला-मुथा नदी संरक्षण : 229.94 करोड़
- ऊर्जा कुशल लिफ्ट सिंचाई परियोजना : 186.44 करोड़

क्या महंगा, क्या सस्ता

आम बजट 2025-26 में सीमा शुल्क कटौती की घोषणा के साथ आयातित जीवन रक्षक दवाएं सस्ती होने वाली हैं। इसके अलावा, कैंसर, दुर्लभ और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, आयातित प्रीमियम कारें और मोटरसाइकिलें भी सस्ती होंगी। दूसरी ओर, बुनियादी सीमा शुल्क में वृद्धि के कारण पूरी तरह से निर्मित इकाइयों के रूप में आयातित इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल (टच स्क्रीन) डिस्प्ले और कुछ बुने हुए कपड़े महंगे हो जाएंगे।

किस मंत्रालय को कितना पैसा आवंटित

मंत्रालय/विभाग	बजट (रुपये में)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	1.37 लाख करोड़
परमाणु ऊर्जा विभाग	3,992 करोड़
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	1.61 लाख करोड़
नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय	2,400 करोड़
कोयला मंत्रालय	501 करोड़
आयुष मंत्रालय	3,992 करोड़
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	18,446 करोड़
दूरसंचार मंत्रालय	1.08 लाख करोड़
उपभोक्ता मंत्रालय	2.15 लाख करोड़
सहकारिता मंत्रालय	1,186 करोड़
कॉरपोरेट मंत्रालय	11,561 करोड़
संस्कृति मंत्रालय	3,360 करोड़
रक्षा मंत्रालय	6.81 लाख करोड़
पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय	5,915 करोड़
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	3,649 करोड़
शिक्षा मंत्रालय	1.28 लाख करोड़
आईटी मंत्रालय	26,000 करोड़
पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	3,412 करोड़
विदेश मंत्रालय	20,000 करोड़
वित्त मंत्रालय	19.3 लाख करोड़
मतस्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय	7,544 करोड़
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4,364 करोड़
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	99,000 करोड़
भारी उद्योग मंत्रालय	7,680 करोड़
गृह मंत्रालय	2.33 लाख करोड़
आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय	96,000 करोड़
सूचना प्रसारण मंत्रालय	4,358 करोड़
जलशक्ति मंत्रालय	99,000 करोड़
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	32,000 करोड़
कानून एवं न्याय मंत्रालय	5,850 करोड़
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय	23,000 करोड़
खनन मंत्रालय	3,000 करोड़
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय	3,350 करोड़
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	26,000 करोड़
पंचायती राज मंत्रालय	1,185 करोड़
संसदीय कार्य मंत्रालय	66 करोड़
कार्मिक मंत्रालय	2,708 करोड़
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	19,000 करोड़
नियोजन मंत्रालय	1,000 करोड़
बंदरगाह, पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय	3,470 करोड़
ऊर्जा मंत्रालय	21,000 करोड़
रेल मंत्रालय	2.55 लाख करोड़
सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय	2.87 लाख करोड़
ग्रामीण विकास मंत्रालय	1.90 लाख करोड़
विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय	38,000 करोड़
कौशल विकास मंत्रालय	6,100 करोड़
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय	14,000 करोड़
अंतरिक्ष मंत्रालय	13,000 करोड़
सांख्यिकी मंत्रालय	5,400 करोड़
इस्पात मंत्रालय	3,362 करोड़
टेक्सटाइल मंत्रालय	5,272 करोड़
पर्यटन मंत्रालय	2,541 करोड़
आदिवासी कल्याण मंत्रालय	14,000 करोड़
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	26,000 करोड़
युवा एवं खेल कल्याण मंत्रालय	3,794 करोड़

मुंबई लोकल के बजट में कटौती, मेट्रो और बुलेट ट्रेन पर जोर

MUTP के लिए 511.48 करोड़ रुपये आवंटित

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

केंद्रीय बजट 2025-26 में मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (MUTP) के लिए 511.48 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार, केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा मिलाकर कुल राशि 1,022.96 करोड़ रुपये होगी।

पिछले बजट के मुकाबले घटा आवंटन

पिछले साल के बजट में MUTP के लिए 789 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि 2023-24 में यह राशि 1,101 करोड़ रुपये थी। इस साल बजट में कमी देखी गई है। हालांकि, पिंक बुक के बाद ही फंड के वास्तविक वितरण की स्थिति स्पष्ट होगी।

बुलेट ट्रेन और मेट्रो को मिला बड़ा बजट

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 4,004 .31 करोड़ रुपये और मुंबई मेट्रो के लिए 1,255 .06 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सूरत से बिलिमोरा तक बुलेट ट्रेन का ट्रायल 2026 में होने की योजना है।

MRVC का खर्च दोगुना होने की उम्मीद

मुंबई रेल विकास निगम (MRVC) ने 2023-24 में MUTP पर 1,874 करोड़ रुपये खर्च किए थे। इस साल मार्च 2025 तक यह खर्च 2,400 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। उपनगरीय रेलवे के तहत कई परियोजनाएं चल रही हैं।

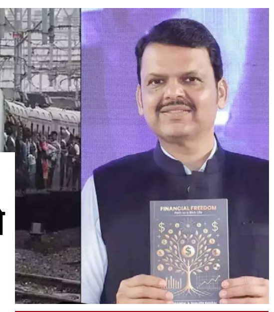

रेल मंत्रालय को 2.52 लाख करोड़ का आवंटन

केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय को 2,52,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता दी है। इससे 200 नई वंदे भारत ट्रेनें, 100 अमृत भारत ट्रेनें, 50 नमो भारत रैपिड रेल और 17,500 सामान्य कोच तैयार किए जाएंगे।

MUTP की प्रमुख योजनाएं:

सीएसएमटी – कुर्ला पांचवीं और छठी लाइन
परेल टर्मिनस का विस्तार
मुंबई सेंट्रल – बोरीवली छठी लाइन
विरार – डहाणू दो नई लाइनें
पनवेल – कर्जत नया कॉरिडोर
एरोली – कलवा लिंक
238 एसी रेक
हार्बर लाइन का बोरीवली तक विस्तार
कल्याण यार्ड का रीडिवेलपमेंट
स्टेशन आधुनिकीकरण और सुरक्षा परियोजनाएं

कोडीनयुक्त कफ सिरप की 147 पेटियां जब्त

पांच आरोपी गिरफ्तार

ठाणे क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई

शरीफ अंसारी | भिवंडी

भिवंडी में ठाणे क्राइम ब्रांच ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 लाख 75 हजार 200 रुपये मूल्य की कोडीनयुक्त कफ सिरप की 147 पेटियां जब्त की हैं। इस ऑपरेशन में कुल 17,640 बोतलें बरामद की गईं। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

मौके पर छापा, आरोपी रंगेहाथ गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच ने ओवली गांव के पास कार्रवाई करते हुए दिलीप हरिराम (28), निवासी भाग्यनगर, भिवंडी को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से 4 बॉक्स (कुल 480 बोतलें) कोडीनयुक्त कफ सिरप बरामद की गई, जिसकी कीमत 86,406 रुपये है।

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

ठाणे क्राइम ब्रांच की शिकायत पर नारपोली पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है।

पूछताछ में हुआ बड़े नेटवर्क का खुलासा

गिरफ्तार दिलीप हरिराम से पूछताछ के दौरान पुलिस को उसके साथी राहुल मिश्रा (वाराणसी) समेत अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। जांच में सामने आया कि आरोपी बिना लाइसेंस के नशे के लिए यह सिरप बेच रहे थे।

अवैध डीलिंग में कई आरोपी शामिल

मामले में ज्योतिप्रकाश हृदय नारायणसी (मुंबई), दिनेश सिंह (अहमदाबाद), और शमसुंदर मिश्रा (वाराणसी) के नाम सामने आए हैं। इन आरोपियों ने 30 लाख 88 हजार 800 रुपये मूल्य के 143 बॉक्स पहले ही बेच दिए थे।

बीजेपी नेता को हाई कोर्ट से झटका

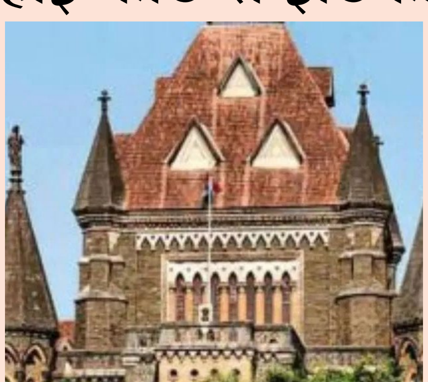

आपराधिक मामलों की वजह से रिन्यू नहीं होगा पासपोर्ट

मुंबई। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता और पूर्व कृषि मंत्री दादा जाधवराव के बेटे पिलाजी सुरसिंह जाधवराव को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की वजह से कोर्ट ने पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार कर दिया। जाधवराव ने अप्रैल में अपने पासपोर्ट की वैधता खत्म होने के बाद अगस्त 2024 में लॉन्ग-टर्म पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया था। हालांकि, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) ने चल रही आपराधिक कार्यवाही का हवाला देते हुए उन्हें कोर्ट की परमीशन लेने का निर्देश दिया।

जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच ने जाधवराव को मंजूरी के लिए आपराधिक अदालत जाने की अनुमति दे दी, लेकिन पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(एफ) के तहत उनके पासपोर्ट रिन्यूअल से इनकार करने के आरपीओ के फैसले को बरकरार रखा। यह अधिनियम आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट जारी करने पर रोक लगाता है। जाधवराव पर 2005 में पुणे के सवाद पुलिस स्टेशन पर हुए हमले में शामिल होने का आरोप है, जहां उन्होंने और 74 अन्य लोगों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। हालांकि, उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन मामला अभी भी लंबित है। इसके बावजूद, उन्हें 2023 में एक साल का पासपोर्ट जारी किया गया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के लिए किया। जाधवराव का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट अभिजीत कुलकर्णी ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है और वह कानूनी प्रक्रिया का पूरा सहयोग करते हैं। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट देने से इनकार करना अनुच्छेद 21 के तहत जाधवराव के यात्रा करने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है, खासकर तब जब उन्हें अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए यूके जाना है। सरकारी वकील लीना पाटिल ने आरपीओ के फैसले का बचाव करते हुए 1993 की सरकारी अधिसूचना का हवाला दिया, जिसके मुताबिक लंबित आपराधिक मुकदमों में पासपोर्ट जारी करने के लिए अदालत की मंजूरी की जरूरत होती है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जाधवराव को आपराधिक अदालत से अनुमति लेनी होगी, जिसे 10 दिनों के अंदर उनके आवेदन पर फैसला करना होगा।

ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

शांतिनगर पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

12 मोबाइल फोन, 12 डेबिट कार्ड, 17 चेकबुक व अन्य दस्तावेज जब्त

डीबीडी संवाददाता | भिवंडी

शांतिनगर पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 12 मोबाइल फोन, 12 डेबिट कार्ड, 17 चेकबुक, 1 पासबुक, 2 पैन कार्ड और 70 हजार रुपये के कीमती सामान जब्त किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें 4 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया।

देशभर में फैला था धोखाधड़ी का जाल

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अलग-अलग राज्यों जैसे बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक के बैंक खातों का उपयोग कर ऑनलाइन धोखाधड़ी कर रहे थे। इनके खातों में 35 लाख रुपये के लेन-देन का खुलासा हुआ है, जिसे फ्रीज कर दिया गया है।

गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई

शांतिनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनायक गायकवाड़ के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक सुरेश चोपड़े और हवलदार रिजवान सैय्यद की टीम ने यह कार्रवाई की। उन्हें गोपनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि फातमानगर इलाके में कुछ लोग फर्जी बैंक खाते खोलकर ऑनलाइन धोखाधड़ी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर अब्दुल रब अब्दुल अहद अंसारी (23), अतीक अहमद जाफर अहमद अंसारी (20), सैफ सलीम अंसारी (17), मोहम्मद बशर जकीउल्लाह अंसारी (20), मोहम्मद जैद अंसार अंसारी (17) को गिरफ्तार किया।

कानूनी कार्रवाई जारी

आरोपियों के खिलाफ अपराध रजिस्टर क्रमांक 135/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4), 3(5) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66(ए), 66(डी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाया जा सके।

बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का सख्त एक्शन

होटल व्यवसायियों को दिए गए कड़े निर्देश

सुशील सिंह | कल्याण

कल्याण-डोंबिवली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। कल्याण के उपायुक्त (डीसीपी) अतुल झेंडे ने सभी पुलिस थानों को निर्देश दिए हैं कि वे होटल व्यवसायियों, लॉजिंग-बोर्डिंग संचालकों, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स और सोसायटियों से बांग्लादेशी श्रमिकों की जानकारी प्राप्त करें।

जानकारी छुपाने पर सख्त कार्रवाई

पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी व्यवसायी ने जानकारी छुपाई और उसके परिसर में बांग्लादेशी श्रमिक पाए गए, तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उठाया गया है।

पृष्ठभूमि जांच के निर्देश

सूत्रों के अनुसार, कई बांग्लादेशी नागरिक होटल, बार, लॉजिंग-बोर्डिंग और निर्माण स्थलों पर काम कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार भी किया है। डीसीपी अतुल झेंडे ने कहा, अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी प्राथमिकता है। सभी व्यवसायियों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां कोई अवैध प्रवासी न हो।

स्थानीय नागरिकों ने किया स्वागत

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद होटल और बार मालिक अपने कर्मचारियों की पृष्ठभूमि जांचने में अधिक सतर्क हो गए हैं। स्थानीय नागरिकों ने भी इस पहल का स्वागत किया है, उनका मानना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शिवसेना नेता पर रॉड से हुआ हमला

जुआ खेलने पर की शिकायत

7 पर मामला दर्ज

डीबीडी संवाददाता | पालघर

पालघर में जुआ खेलने की शिकायत करने पर 75 वर्षीय शिवसेना नेता पर उनके ही घर में लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 29 जनवरी को जौहर में हुए हमले के लिए पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।

शिवसेना नेता पर रॉड से की किया हमला

उन्होंने बताया कि शिवसेना की जिला इकाई के उपप्रमुख विजय घोलप ने जुआ खेलने की शिकायत अधिकारियों से की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गतिविधि को रुकवा दिया। आरोपी 29 जनवरी की शाम को घोलप के घर पहुंचे और लोहे की रॉड से उन पर हमला कर दिया। हमले में घोलप को गंभीर चोटें आईं और उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

अधिकारी ने बताया कि घोलप की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 109 (हत्या का प्रयास), 189 (दो) (अवैध रूप से एकत्र होना), 190 (समान उद्देश्य के लिए किया गया अपराध), 191 (दो) (दंगा) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई

8 यात्रियों से करोड़ों का सोना, हीरा और ड्रग्स बरामद

मुंबई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (सीएसएमआई) पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली है। 28 से 31 जनवरी के बीच कस्टम की टीम ने करोड़ों रुपये का ड्रग्स, सोना और हीरा बरामद किया है। अलग अलग 6 मामलों में कार्रवाई करते हुए 8 यात्रियों को गिरफ्तार भी किया गया है। सूत्रों ने बताया कि कस्टम की टीम ने 2 मामलों में गांजे की खेप पकड़ी। 50 ।116 किलोग्राम गांजे की कीमत 50 ।116 करोड़ रुपये बताई गई है। एक मामले में 551 ।10 कैरेट वजन के हीरे जब्त किए। हीरे की कीमत 93 ।85 लाख रुपये है। 3 अन्य मामलों में1 ।549 करोड़ रुपये का 2 ।073 किलोग्राम सोना तस्करों के पास बरामद किया गया। सूत्रों ने बताया कि स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने रियाद और मस्कट से आने वाले 2 यात्रियों को रोका। तलाशी लेने पर सोने की छड़ बैग और सोने की धूल यात्री के शरीरे में होने का पता चला। दोनों यात्रियों के पास से 64 ।50 लाख रुपये का 863 ग्राम सोना बरामद किया गया।

कस्टम विभाग की टीम को मिली सफलता

कस्टम अधिकारियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर बैंकॉक जा रहे 1 यात्री को रोका। तलाशी लेने पर यात्री के पास से 551 ।10 कैरेट का हीरा बरामद किया। हीरे की कीमत 93 ।85 लाख रुपये बताई गई है। यात्री के शरीर का स्कैनिंग करने पर हीरे की मौजूदगी का खुलासा हुआ। कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए 5 यात्रियों को जांच के लिए एयरपोर्ट पर रोका। 2 मामलों में लगभग 50 ।116 करोड़ रुपये कीमत की ड्रग्स बरामद की गई। सूत्रों ने बताया कि ड्रग्स हाइड्रोपोनिक वीड या गांजे का कुल वजन लगभग 50 ।116 किलोग्राम था।

ट्रॉली बैग की तलाशी लेने पर पारदर्शी प्लास्टिक के पैकेट मिले। वैक्यूम सीलबंद पैकेट के अंदर से गांजे की खेप निकली। कस्टम की टीम ने बैंकॉक की फ्लाइट से उतरे पांचों यात्रियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम में गिरफ्तार कर लिया। दूसरे मामले में विशेष इनपुट के आधार पर दुबई से आए 2 यात्रियों को रोका गया। एयरपोर्ट पर चेकिंग में यात्रियों के शरीर से सोने की धूल बरामद हुई। सोने की धूल का वजन 1 ।210 किलोग्राम और कीमत 90 ।42 लाख रुपये है।

रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया लिपिक

ठाणे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने की कार्रवाई

डीबीडी संवाददाता | कल्याण

कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका के बाजार और लाइसेंस विभाग के लिपिक प्रकाश काशिनाथ धिवर को ठाणे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (ACB) ने शुक्रवार को डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। यह कार्रवाई तक्रारकर्ता की शिकायत पर की गई, जिसने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में मटन बिक्री का लाइसेंस स्वीकृत करने के एवज में लिपिक ने रिश्वत मांगी थी।

जाल बिछाकर रंगे हाथ पकड़ा गया

शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की टीम ने नगर निगम कार्यालय में जाल बिछाया। जैसे ही तक्रारकर्ता ने लिपिक को रिश्वत की रकम सौंपी, टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रकाश धिवर को रंगे हाथ पकड़ लिया। इस कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक शिवराज पाटील के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक संतोष अंबिके की टीम ने किया। मामले में लिपिक के वरिष्ठ अधिकारियों के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। इसलिए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है।

दो लाख से शुरू होकर डेढ़ लाख पर बनी बात

तक्रारकर्ता के अनुसार, लिपिक धिवर ने शुरुआत में दो लाख रुपये की मांग की थी, जो तक्रारकर्ता के लिए संभव नहीं था। बातचीत के बाद लिपिक ने डेढ़ लाख रुपये में सहमति जताई। इसके बाद तक्रारकर्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई।

भवन निर्माण के लिए अब राज्य सरकार से मिलेगी अनुमति

6 महीने से रुकी परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

सांसद नरेश म्हस्के और किशोर पाटकर के प्रयास सफल

धर्मेंद्र उपाध्याय | ठाणे

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और एमआईडीसी के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली निर्माण परियोजनाओं के लिए अब राज्य सरकार की पर्यावरण नियंत्रण समिति से अनुमति लेना संभव होगा।

अब राज्य स्तर पर मिलेगी मंजूरी

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और मीरा भयंदर जैसे शहरी इलाकों में 20,000 से 1,50,000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र वाली परियोजनाओं को अब केंद्रीय स्तर की बजाय राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी। इससे निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और प्रक्रियाएं सरल होंगी।

अगस्त 2024 के फैसले से रुकी थीं परियोजनाएं

अगस्त 2024 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने फैसला दिया था कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति अनिवार्य होगी। इस फैसले से निर्माण क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा हो गई थी, जिससे कई पुनर्विकास और नई परियोजनाएं पिछले छह महीनों से ठप पड़ी थीं। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सांसद नरेश म्हस्के और शिवसेना नवी मुंबई जिला प्रमुख किशोर पाटकर ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे से मुलाकात की। लगातार प्रयासों के बाद केंद्रीय मंत्रालय के संयुक्त सचिव रजत अग्रवाल ने 29 जनवरी 2025 को एक नई गजट अधिसूचना जारी की, जिससे राज्य स्तर पर मंजूरी का रास्ता साफ हुआ।

निर्माण क्षेत्र और नागरिकों को मिलेगी राहत

इस फैसले से न केवल डेवलपर्स को राहत मिलेगी बल्कि फ्लैट खरीदारों और पुनर्विकास परियोजनाओं में रहने वाले नागरिकों को भी फायदा होगा। किशोर पाटकर ने इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे और सांसद नरेश म्हस्के का आभार व्यक्त किया।

महायुति ने मनाया मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट का जश्न

डीप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने की प्रशंसा

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र की महायुति सरकार को केंद्र का यह बजट बहुत ही पसंद आया है। बजट की सराहना करते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं अजीत पवार सहित कई अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार माना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश का बजट पेश किया। बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करने की बड़ी घोषणा करके उन्होंने मध्यम वर्ग के करदाताओं को सबसे बड़ी राहत दी है। सरकार के इस अनपेक्षित निर्णय का लोगों ने सहर्ष स्वागत किया है। शनिवार को पेश किए गए बजट में नई कर प्रणाली के अनुसार आयकर स्लैब में परिवर्तन किया गया है। नई कर व्यवस्था के अनुसार 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगाने की घोषणा की गई है। दावा किया जा रहा है कि इस लाभ मध्यमवर्गीय नौकरीपेशा लोगों को मिलेगा।

घर-घर में दिखाई देंगे लक्ष्मी के पदचिह्न : उपमुख्यमंत्री शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पर कहा है कि बजट में आम नौकरीपेशा वर्ग को जो राहत मिली है, उसे अभूतपूर्व ही कहा जा सकता है। डीसीएम शिंदे ने केंद्रीय बजट 2025-26 का स्वागत करते हुए कहा कि 12 लाख रुपये तक की आय पर पूर्ण कर छूट के कारण अब देवी लक्ष्मी के पदचिन्ह हर घर में दिखाई देंगे। केंद्र सरकार का बजट इस बात की गारंटी है कि देश के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा देखा गया विकसित भारत का सपना साकार होगा। बजट में आम नौकरी पेशा वर्ग को जो राहत मिली है, उसे अभूतपूर्व ही कहा जा सकता है। मैं आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करनेवाला सर्वांगीण सुंदर बजट पेश करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण को बधाई देता हूं। मैं महाराष्ट्र के सभी कर्मचारियों की ओर से उनका आभार मानता हूं।

विकसित भारत और आर्थिक महाशक्ति बनने का आधार : उपमुख्यमंत्री पवार

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजीत पवार ने कहा कि 12 लाख तक की आय कर-मुक्त होने से करोड़ों मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। महाराष्ट्र के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार माना। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए निधि से बुनियादी परियोजनाओं को बल मिलेगा और मजबूत नींव रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों, श्रमिकों, व्यापारियों, उद्यमियों, महिलाओं, और छात्रों को अवसर देता बजट, आम आदमी पर ध्यान केंद्रित है। बजट का स्वागत करते हुए अजीत ने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए यह बजट एक बड़ा तोहफा है, क्योंकि 12 लाख तक की आय अब कर-मुक्त हो गई है। नए कर प्रणाली के तहत, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं को 80,000 की छूट मिलेगी, जिससे 100% कर राहत प्राप्त होगी। 18 लाख की आय वालों को 70,000 की कर कटौती, जबकि 25 लाख की आय वालों को 1.25 लाख की कर राहत मिलेगी। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है, जो एक स्वागत योग्य निर्णय है। कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की 36 आवश्यक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है, जिससे वे अब अधिक किफायती होंगी। मोबाइल फोन भी सस्ते होंगे, जिससे देश के हर नागरिक को लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र को बजट में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि मिली है।

भारत को विकास के मार्ग पर ले जाने वाला बजट : माधुरी मिसाल

राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने बजट पर कहा यह विकसित भारत को विकास के मार्ग पर ले जाने वाला बजट है। इस बजट ने महिला, किसान, गरीब, युवा और मध्यमवर्गीय घटकों को बड़ी सौगात दी है। देश के मध्यमवर्ग को 12 लाख तक की कर मुक्ति, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख, साथ ही 1 करोड़ 70 लाख किसानों को 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' का लाभ, देश में हरित ऊर्जा, ईवी और एआई तकनीक को बड़ा प्रोत्साहन, दालों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना, और आगामी पांच वर्षों में देश में चिकित्सा शिक्षा की 75,000 अतिरिक्त सीटें, ऐसे हर वर्ग को समृद्ध करने वाला और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ले जाने वाला यह एक समग्र केंद्रीय बजट है।

'शिवसेना के विभाजन पर दुख'

शिंदे गुट के मंत्री संजय शिरसाठ ने दोनों गुटों के एकजुट होने की इच्छा जताई

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल के बीच शिंदे गुट के मंत्री संजय शिरसाठ ने शिवसेना के विभाजन पर दुख जताते हुए कहा, "अगर मौका मिला तो मैं दोनों शिवसेना पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश करूंगा।" हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान शिरसाठ ने स्पष्ट किया कि उनके बयान की गलत व्याख्या की गई। उन्होंने कहा, "हमारा मानना था कि शिवसेना का विभाजन नहीं होना चाहिए। यह सोचना गलत है कि मैं कोई अलग प्रयास कर रहा हूं।"

शिरसाठ ने कहा कि सत्ता के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने का फैसला गलत था।

Change Of Name

I HAVE CHANGED MY NAME FROM OLD NAME VINOD RAMKRISHNA SHUKLA TO NEW NAME VINOD KUMAR RAMKRISHNA SHUKLA AS PER DOCUMENT

पश्चिम रेलवे

सहायक ट्रांसफार्मर का प्रतिस्थापन

एडीईई/टीआरडी/बीएल, पश्चिम रेलवे, दिनांक 29.01.2025 को **निविदा सूचना संख्याः ईएल-टीआरडी-डब्लू-118-23-24-12-आर-2 आमंत्रित करते हैं। कार्य का नामः** मुंबई डिवीजन के विरार-संजन सेक्शन में एमएसडीएसएसी कार्य के लिए रिले हट के स्थान के संबंध में सहायक ट्रांसफार्मर का प्रतिस्थापन। **कार्य की अनुमानित लागतः** 37,70,920/- **ईएमडीः** 75,400/- **जमा करने की तिथि और समयः** 21.02.2025, 15:00 बजे तक। **खुलने की तिथि और समयः** 21.02.2025 को 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर जाएँ, मैनुअल ऑफ़र पर विचार नहीं किया जाएगा। 1032

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

किरीट सोमैया ने बांग्लादेशियों के खिलाफ सौंपे सबूत

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र देने वालों पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की

मुंबई/नासिक। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मांग की है कि मालेगांव में बांग्लादेशियों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मुहैया कराने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। सोमैया ने विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम को सबूत सौंपे, जिसमें दावा किया गया कि कम से कम 100 बांग्लादेशियों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर जन्म प्रमाण पत्र हासिल किए हैं। इस्माइल नामक एक व्यक्ति ने कथित तौर पर जन्म का कोई सबूत पेश किए बिना जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जिसे राजस्व विभाग ने नोट किया था। सोमैया ने मालेगांव तहसील कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर धोखाधड़ी में मिलीभगत का आरोप लगाया, जिसके कारण उन्होंने देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने जिला कलेक्टर के कार्यालय में डॉ. गेडाम से मुलाकात की और बाद में मीडिया प्रतिनिधियों से बात की उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है कि मालेगांव में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं ने जन्म प्रमाण पत्र हासिल किए और बाद में भारतीय नागरिकता और आधार कार्ड हासिल कर लिए।

बांग्लादेशी नागरिकों को गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र दिए

भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के मालेगांव में बांग्लादेशी नागरिकों को गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड दिए गए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इसमें तत्कालीन तहसीलदार और अन्य कर्मचारी भी शामिल थे।

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

सोमैया ने डॉ. प्रवीण गेडाम को सबूत सौंपे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्तक्षेप के कारण यह मामला सामने आया है और राज्य में 3977 लोगों को ऐसे जन्म प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इस मामले में डॉ. गेडाम ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पश्चिम रेलवे

कचरा उठाने का कार्य

वरिष्ठ डीईएन (दक्षिण), पश्चिमी रेलवे, मुंबई सेंट्रल, मुंबई 400008, **निविदा सूचना संख्याः बीसीटी/24-25/278, दिनांकः 31.01.2025 आमंत्रित करते हैं। कार्य और स्थानः** चर्चगेट - विरार खंडः एसएसई (पी. वे) अंधेरी खंड के अंतर्गत माहिम दक्षिण यार्ड में कचरा उठाना। **कार्य की अनुमानित लागतः** 86,79,029.56 **ईएमडीः** 1,73,600/- **जमा करने की तिथि और समयः** 25.02.2025, 15:00 बजे तक। **खुलने की तिथि और समयः** 25.02.2025 को 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर जाएँ। 1037

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

मरम्मत कार्य

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (कोचिंग), पश्चिमी रेलवे, मुंबई सेंट्रल, मुंबई -400008, **निविदा सूचना संख्याः WR-MMCT 0ECOA (ECTD)/40/2024 0/0 SRDEE/CHG/ MMCT/WR (कंप्यूटर संख्या 592386) आमंत्रित करते हैं। कार्य का नामः** मेसर्स कमिंस डीजल इंजन रेडिएटर CPCB-I-मॉडल KTA19G4 की मरम्मत, फिटमेंट, परीक्षण और कमीशनिंग। **कार्य की अनुमानित लागतः** 4,99,966/-**बोली सुरक्षाः** 10000/- **प्रस्तुत करने की तिथि और समयः** 27.02.2025, 15:00 बजे तक। **खुलने की तिथि और समयः** 27.02.2025 को 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर जाएँ। 1028

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

सामग्री प्रबंधन विभाग

विभिन्न सामग्री आपूर्ति

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना संख्या S/08/2025 दिनांक 31.01.2025

क्र.सं.	वस्तु का संक्षिप्त विवरण	मात्रा	T.O.D.
58	ड्रग एल्यूटिंग कोरोनरी स्टेंट सिस्टम	225 नग	20-फरवरी-25
59	सर्वोप्लेक्स SHC-120 (IOCL) ग्रीस WAG-9/WAP-7 लोको के ट्रैक्शन मोटर बियरिंग के लिए।	12956 किग्रा	26-फरवरी-25
60	हर्मेटिकली सीलबंद स्क्रॉल कंप्रेसर	295 नग	27-फरवरी-25
61	सस्पेंशन ट्यूब और इसके असेंबली घटक	480 सेट	28-फरवरी-25
62	लंबे समय तक चलने वाला साइड बफर असेंबली	180 नग	28-फरवरी-25
63	स्पेयर प्लासर मेक के लिए दो साल के लिए दर अनुबंध	1 सेट	28-फरवरी-25
64	एक्सल बॉक्स बेयरिंग (CRU-150) WAG 9HC/WAP-7 के लिए	212 नग	01-मार्च-25
65	हीटलेस ट्विन टावर एयर ड्रायर	30 नग	03-मार्च-25
66	वैक्यूम सर्किट ब्रेकर	80 नग	03-मार्च-25
67	जनरेटर कार के लिए प्राथमिक स्प्रिंग इनर।	805 नग	03-मार्च-25
68	SA-9 स्वतंत्र ब्रेक वाल्व	160 नग	04-मार्च-25
69	डीजल लोको स्टार्टर बैटरी 8V,500AH	578 नग	20-मार्च-25

शुद्धिपत्र

कृपया निविदा सूचना संख्या **S-70-2024** दिनांकः 30.12.2024 के लिए नियत तिथि को "13.02.2025" के रूप में पढ़ें। क्रमांक 755

विस्तृत सूचना ईएमडी, खरीद प्रतिबंध और विस्तृत निविदा शर्तों के बारे में, कृपया वेबसाइट www.ireps.gov.in और www.wr.indianrailways.gov.in पर जाएं। 1040

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly | हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

मुंह पर ताला लगाना नहीं मंजूर: छगन भुजबल

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री और अजित पवार की एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वह जहां अजित पवार पर लगातार निशाना साध रहे हैं तो वहीं बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। शुक्रवार को भुजबल ने कहा था कि मुझे राज्यपाल बनाया जाना मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पद एक तरह से मुंह पर ताला लगाने जैसा है और यह मेरी शख्सियत से मेल नहीं खाता है।

ऐसी चर्चा चल रही है कि महायुति से उन्हें राज्यसभा सांसद या किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। हालांकि भुजबल ने शनिवार को केंद्रीय बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट भारत की भविष्य की आर्थिक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसमें मध्यम वर्ग, किसानों, उद्योग और स्टार्टअप क्षेत्र के लिए विभिन्न लाभकारी प्रावधान किए गए हैं।

रिजेक्ट कर दिया ऑफर

पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में भुजबल ने राज्यपाल पद का ऑफर मिलने से पहले ही उसे रिजेक्ट कर दिया। अजीत पवार की एनसीपी में भुजबल सबसे सीनियर लीडर हैं, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। इस वजह से वे नाराज चल रहे हैं। मुजबल ने मीडिया से कहा था कि मुझे राज्यपाल बनाना मेरे मुंह पर ताला लगाने जैसा है। राज्यपाल बनने के बाद मैं क्या करूंगा। मेरा काम गरीबों की समस्याओं को हल करना है, उनके लिए लड़ना है। उन्होंने पूछा था कि क्या मैं राज्यपाल बनकर उन समस्याओं का समाधान कर सकूंगा?

गवर्नर बनने को छगन भुजबल नहीं राजी

भुजबल ने कहा कि मैं राज्यपाल के पद का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। भुजबल ने यह भी कहा कि बीजेपी के साथ अजीत पवार की एरनसीपी का गठबंधन है, शादी नहीं। उन्होंने अपने इस बयान से साफ़ किया है कि यह युति परमानेंट नहीं हैं। आने वाले दिनों में रास्ते अलग भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनने के बाद नागपुर में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। इसमें एनसीपी से भुजबल को जगह नहीं मिली थी। इसके बाद वह नासिक चले गए थे और कहा था कि जहां नहीं चैना, वहां नहीं रहना। इसके बाद से भुजबल नाराज बताए जा रहे हैं।

पश्चिम रेलवे

विद्युत शक्ति कार्य

वरिष्ठ डीईई/पी/बीसीटी, पश्चिमी रेलवे, मुंबई सेंट्रल, **निविदा सूचना संख्याः ईएल-81-79-18-डब्ल्यूए-50, दिनांक 29.01.2025 को आमंत्रित करते हैं। कार्य और स्थानः** सचिन - लूप लाइन नंबर 1 पर आइलैंड प्लेटफॉर्म, पीएफ नंबर 2 और होम प्लेटफॉर्म के विस्तार और उत्थान के संबंध में विद्युत (पावर) कार्य। **कार्य की अनुमानित लागतः**1,04,90,903/- **ईएमडीः** 2,02,500/- **जमा करने की तिथि और समयः** 04.03.2025, 15:00 बजे तक। **खुलने की तिथि और समयः** 04.03.2025 को 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर जाएं। 1034

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

सार्वजनिक सूचना

किले में उत्तरी एमसीजीएम फुट ओवर ब्रिज (पोइसर नाला) का बंद होना

कारशेड लाइन और एसटीए लाइन (जीपी 31/2-3) के बीच किले कारशेड के पास उत्तरी एमसीजीएम फुट ओवर ब्रिज (पोइसर नाला) के स्तंभ नई प्रस्तावित 5वीं लाइन के संरेखण का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए स्वीकृत योजना के अनुसार फुट ओवर ब्रिज के समान संरेखण में कारशेड लाइन और अप थ्रू लाइन के बीच स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। **एमसीजीएम फुट ओवर ब्रिज सार्वजनिक उपयोग के लिए 06.02.2025 से 31.03.2025 तक बंद रहेगा। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए अत्यधिक खेद है।**

पश्चिम रेलवे
www.wr.indianrailways.gov.in 1038

हमें लाइक करें: www.facebook.com/WesternRly | हमें फॉलो करें: www.twitter.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक-प्रबंधक, मुंबई सेंट्रल मंडल, पश्चिम रेलवे
मंडल रेलवे प्रबंधक, वाणिज्यिक विभाग, एनएफआर अनुभाग मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400 008

कार्य-मुंबई मंडल में विभिन्न एनएफआर मीडिया के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करना।

नीलामी सूची क्रमांक	नीलामी शुरू (सभी लॉट)
MMCT-ADVT-24-72	17.02.2025, 15:00:00

क्र. सं.	लॉट संख्या	स्थान/क्षेत्र	दिन	ई-नीलामी की अंतिम तिथि और समय
1	ADVT-BCT-GMN-OSN-382-24-1 (विज्ञापन-स्टेशन परिसर में (गैर-डिजिटल))	गोरेगांव (GMN) स्टेशन पर पटरियों के बीच रैलिंग पर 3 साल की अवधि के लिए थोक विज्ञापन अधिकार	1096	17.02.2025. 15:30:00
2	ADVT-BCT-BVI-OSN-384-24-1 (विज्ञापन-स्टेशन परिसर में (गैर-डिजिटल))	बोरीवली (BVI) स्टेशन पर पटरियों के बीच रैलिंग पर 3 साल की अवधि के लिए थोक विज्ञापन अधिकार	1096	17.02.2025, 15:40:00
3	ADVT-BCT-BYR-OSN-387-24-1 (विज्ञापन-स्टेशन परिसर में स्टेशन परिसर (गैर-डिजिटल))	भायंदर (BYR) स्टेशन पर पटरियों के बीच रेलिंग पर 3 साल की अवधि के लिए थोक विज्ञापन अधिकार	1096	17.02.2025 15:50:00
4	ADVT-BCT-KILE-OSN-383-24-1 (स्टेशन परिसर पर विज्ञापन (गैर-डिजिटल))	कांदिवली (KILE) में पटरियों के बीच रेलिंग पर 3 साल की अवधि के लिए थोक विज्ञापन अधिकार	1096	17.02.2025. 16:00:00
5	ADVT-BCT-GTR-OSN-157-23-2 (स्टेशन परिसर पर विज्ञापन (गैर-डिजिटल))	ग्रांट रोड (GTR) 1006 स्टेशन पर तीन साल की अवधि के लिए थोक विज्ञापन अधिकार	1096	17.02.2025 16:10:00
6	ADVT-BCT-JOS-OSN-380-24-1 (स्टेशन परिसर पर विज्ञापन (गैर-डिजिटल))	जोगेश्वरी (JOS) 1096 में थोक विज्ञापन अधिकार 3 साल की अवधि के लिए पटरियों के बीच रेलिंग पर स्टेशन	1096	17.02.2025 16:20:00
7	स्टेशन ADVT-BCT-MIRA-OSN-386-24-1 पर (विज्ञापन-परिसर (गैर-डिजिटल))	मीरा रोड रोड (MIRA) (MIKA) 1096 पर थोक विज्ञापन अधिकार 3 साल की अवधि के लिए पटरियों के बीच रेलिंग पर स्टेशन	1096	17.02.2025 16:30:00
8	स्टेशन ADVT-BCT-CYR-OSN-369-24-1 पर (विज्ञापन परिसर (गैर-डिजिटल))	प्लेटफ़ॉर्म कॉपिंग दीवार और डिवाइडर पर स्टेशन चर्नीरोड (CYR) पर बाड़ लगाने पर थोक विज्ञापन अधिकार 3 साल की अवधि के लिए	1096	17.02.2025, 16:40:00
9	ADVT-BCT-DIC-OSN-385-24-1 (विज्ञापन स्टेशन "प्रिनिस (गैर-डिजिटल))	दहिसर (DIC) स्टेशन 1096 पर थोक विज्ञापन अधिकार 3 वर्ष की अवधि के लिए पटरियों के बीच	1096	17.02.2025. 16:50:00
10	ADVT-BCT-NSP-OSN-390- 24-1 (स्टेशन परिसर में विज्ञापन (गैर-डिजिटल))	नालासोपारा (NSP) 1096 स्टेशन पर पटरियों के बीच रैलिंग पर 3 वर्ष की अवधि के लिए विज्ञापन अधिकार	1096	17.02.2025 17:00:00
11	ADVT-BCT-RMAR-OSN-381-24-1 (स्टेशन परिसर में विज्ञापन (गैर-डिजिटल))	राम मंदिर (RMAR) स्टेशन पर पटरियों के बीच रेलिंग पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बल्क विज्ञापन अधिकार	1096	17.02.2025 17:10:00
12	ADVT-BCT-BSR-OSN-389-24-1 (स्टेशन परिसर में विज्ञापन (गैर-डिजिटल))	वसई रोड (BSR) स्टेशन पर पटरियों के बीच रेलिंग पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बल्क विज्ञापन अधिकार	1096	17.02.2025 17:20:00
13	ADVT-BCT-NIG-OSN-388-24-1 (स्टेशन परिसर में विज्ञापन (गैर-डिजिटल))	नायगांव (NIG) स्टेशन पर पटरियों के बीच रेलिंग पर 3 साल की अवधि के लिए थोक विज्ञापन अधिकार	1096	17.02.2025 17:30:00

नोटः संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे IREPS वेबसाइट (**www.ireps.gov.in**) पर ई-नीलामी लीजिंग मॉड्यूल देखें। लॉट के अनुसार विवरण नीचे दिए गए कैटलॉग में उपलब्ध हैं। 1039

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly | हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

बहुउद्देशीय स्टॉल (एमपीएस) का प्रावधान

मुंबई सेंट्रल डिवीजन के ए1, सी और डी श्रेणी के स्टेशनों पर बहुउद्देशीय स्टॉल (एमपीएस) के प्रावधान के लिए ई-नीलामी डीआरएम (सी), बीसीटी द्वारा फरवरी-2025 के महीने के लिए **ए1. सी और डी** श्रेणी के स्टेशनों पर बहुउद्देशीय स्टॉल के लिए आयोजित की जाने वाली ई-नीलामी के लिए आमंत्रित की गई है।

1. नीलामी कैलेंडर संख्याः BCT-CTG-MPS-25

क्र.सं.	स्टेशन	स्थान
1	मुंबई सेंट्रल	कॉनकोर्स हॉल
2	वानगांव	पीएफ नंबर 1पर पिलर संख्या 19 और 20 के बीच
3	मुंबई सेंट्रल लोकल	पीएफ नंबर 3/4 पर पिलर संख्या 16 और 17 के बीच
4	अमलसाड	पीएफ नंबर 1 पर सीएच 285 से 290 मीटर पर
5	मुंबई सेंट्रल	पीएफ नंबर 3/4 पर पोल नंबर 13 और 14 के बीच
6	मुंबई सेंट्रल लोकल	पीएफ नंबर 1/2 पर पिलर नंबर 10 और 11 के बीच
7	सफाले	पीएफ नंबर 2 पर पिलर नंबर 25 और 26 के बीच
8	अंधेरी	ईस्ट कॉन्कोर्स
9	बोईसर	कॉन्कोर्स हॉल
10	चर्चगेट	एंट्री/एग्जिट गेट नंबर 4 के बगल में आसन्न एरिया मैनेजर
11	भायंदर	ऑफिस पीएफ नंबर 6 पर पिलर नंबर 14 और 15 के बीच
12	नालासोपारा	पीएफ नंबर 2/3 पर 18 और 19 के
13	संजन	पीएफ नंबर 1 के सामने वेटिंग हॉल

क्षेत्रफल (वर्ग फीट): 60, ई-नीलामी की तिथिः 12.02.2025,
ई-नीलामी का समय-(घंटे): 12:00 बजे
नोटः संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे IREPS वेबसाइट (**www.ireps.gov.in**) पर ई-नीलामी लीजिंग मॉड्यूल देखें। लॉट के अनुसार विवरण वहाँ उल्लिखित कैटलॉग के अंतर्गत उपलब्ध हैं। 1033

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

मध्य रेल

ई-निविदा सूचना क्रमांक. NIT /01/25/06 दिनांक 30 जनवरी 2025

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से, प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक, मध्य रेलवे निम्नलिखित वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं।

क्रमांक	निविदा क्रमांक	विवरण	मात्रा	नियत तिथि
1	18243494ए	वुडवर्ड गवर्नर के लिए ओवरहालिंग किट	54 नग	17-फ़रवरी-25
2	27253283	संपर्कों का सेट	424 सेट	17-फ़रवरी-25
3	80252249	ट्रैक्शन मोटर बेयरिंग के लिए सर्वोप्लेक्स SHC-120 (IOCL) ग्रीस	9800 किग्रा	17-फ़रवरी-25
4	27253231	पेंटोग्राफ किसी भी नाप का नक्शा इत्यादि खिंचने का यंत्र	64 नग	20-फ़रवरी-25
5	27254665	पेंटोग्राफ के लिए बो असेंबली	63 नग	20-फ़रवरी-25
6	27253007	ब्रेक गियर भागों का सेट	25 सेट	24-फ़रवरी-25
7	38241347	माल स्टॉक के लिए सामान्य पाइप ब्रेकेट और नियंत्रण जलाशय के बिना पूर्ण वितरक वाल्व	458 नग	24-फ़रवरी-25
8	71245101ए	आर्थोपेडिक विभाग के लिए रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए रोबोटिक प्रणाली की खरीद	02 नग	28-फ़रवरी-25
9	27253964	डिस्क ब्रेक व्यवस्था	10 सेट	03-मार्च-25
10	50243093ए	इलेक्ट्रिक प्वाइंट मशीन	30 नग	10-मार्च-25
11	51246026	आरडीएसओ के लिए व्यापक प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर	2516690 नग	20-फ़रवरी-25

नोट: उपरोक्त सभी निविदाएं ई-निविदाएं हैं और सभी निविदाकारों से अनुरोध है कि वे अपनी बोलियां IREPS वेबसाइट https://www.ireps.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा करें। उपर्युक्त निविदाओं और अन्य आपूर्ति निविदाओं के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया IREPS वेबसाइट जाएं।

कृते प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक 745

खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

संपादकीय

बजट : उम्मीदें और आशंकाएं

अंततः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के जरिये मध्य वर्ग को बड़ी राहत दी। इसकी संभावना भी जताई जा रही थी। इसलिए और भी, क्योंकि आर्थिक सर्वे के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं प्रार्थना करता हूं कि मां लक्ष्मी देश के गरीब और मध्य वर्ग पर अपनी कृपा बनाए रखें। वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स न देने की घोषणा कर सचमुच कृपा कर दी। इसके अनुकूल नतीजे देखने को मिलने चाहिए। अर्थव्यवस्था को न केवल बल मिलना चाहिए, बल्कि वह कहीं तेज गति से बढ़नी चाहिए। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि आर्थिक सर्वे जहां यह कह रहा है कि आगामी वित्त वर्ष में आर्थिक विकास की दर 6.3 से 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, वहीं देश को विकसित बनाने के लिए कम से कम एक दशक तक आठ प्रतिशत विकास दर की आवश्यकता है। आखिर यह आवश्यकता कैसे पूरी होगी? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि बजट में ऐसे ठोस उपाय नहीं किए गए, जिससे आठ प्रतिशत विकास दर को हासिल किया जा सके। देश को विकसित बनाने में सहायक बनने वाली तेज विकास दर को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता, जब तक हमारे उद्योग-धंधे वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम नहीं बनते। उन्हें इस प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए उत्कृष्टता भी हासिल करनी होगी, क्योंकि वे तभी वैश्विक बाजार की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे। यह अनिवार्य है कि बड़े उद्योगों के साथ हमारे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के उत्पादों की गुणवत्ता विश्वस्तरीय हो। उनकी उत्पादन लागत भी विश्वस्तरीय होनी चाहिए। यह सही है कि बजट में यह प्रविधान किया गया है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कहीं आसानी से ज्यादा कर्ज मिल सकेगा, लेकिन उनकी समस्या कर्ज नहीं, वह तकनीक है, जिसके अभाव में उनके उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान नहीं बना पा रहे हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सशक्त होने से केवल देश को आत्मनिर्भर बनाने में ही सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि रोजगार के कठिन सवाल को हल करने में भी आसानी होगी। आर्थिक सर्वे यह कह रहा था कि मौजूदा माहौल में पारंपरिक आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाना प्रासंगिक नहीं, लेकिन बजट यह सुनिश्चित नहीं करता कि ऐसी सभी नीतियों का परित्याग किया जा रहा है। बजट में सामाजिक विकास की योजनाओं पर धन का आवंटन बढ़ाना समय की मांग थी, लेकिन अच्छा होता कि बजट यह संदेश भी देता कि लोगों को आत्मनिर्भर न बनाने वाली लोकलुभावन नीतियां सही नहीं। जब लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी देश भी आत्मनिर्भर होगा। निःसंदेह बजट बेहतर कल की उम्मीदें जगा रहा है, लेकिन वह उन आशंकाओं को दूर करता नहीं दिखता, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारणों से उभर रही हैं।

लोक लुभावन भी और राजनीतिक भी

उमेश चतुर्वेदी

बजट की तैयारियों के बीच सोशल मीडिया पर एक खबर जुगनू की तरह आई और तत्काल लुप्त हो गई थी। जिसने जुगनू के उस प्रकाश को देखा और उसके संकेतों को समझने की कोशिश की थी, उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि आम बजट में क्या होने जा रहा है। सोशल मीडिया पर आए उस समाचार में कहा गया था कि केंद्र सरकार के प्रति मध्य वर्ग पहले की तरह उत्साही नहीं है। किंचित वह केंद्र सरकार के कामकाज और सरकार की ओर से हो रही बेरूखी से वह परेशान और निराश है। सोशल मीडिया पर मध्य वर्ग की ऐसी प्रतिक्रियाओं पर मोदी की नजर रहती है। इसे देखते हुए उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा था कि वे लोगों से सीधा संवाद करें। सोशल मीडिया यही खबर थी। लेकिन इस खबर के संकेत साफ थे। आम बजट में मध्य वर्ग को राहत मिलने के आसार तभी दिखने लगे थे। निर्मला सीतारमण की ओर से बारह लाख 75 हजार रूपए तक की आय पर मिली आयकर छूट को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कुछ महीनों बाद देश की राजनीति की धड़कन माने जाने वाली मगध की धरती यानी बिहार में भी चुनाव होना है। निर्मला सीतारमण की ओर से मिली आयकर छूट से सरकारी कर्मचारियों की भी राजधानी मानी जाने वाली दिल्ली चुनाव पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार के बजट से खुश नहीं हैं और कह रहे हैं कि इस बजट से आम लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। इस बजट में बिहार को बहुत कुछ मिला है। निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्ताव में बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का एलान किया है। इससे बिहार के मखाना किसानों को राहत मिलने के आसार है। इसके उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग के अवसर बढ़ेंगे। जाहिर है कि इसका सीधा फायदा बिहार के ही लोगों को मिलेगा। बजट प्रस्तावों में मखाना निकालने के काम में लगे लोगों के लिए भी सरकारी राहत की बात की गई है। यानी मखाना उत्पादक, उसके वितरक और उसके कामगार, सबको राहत और मौका देने की बात की गई है। प्रस्तावित मखाना बोर्ड की एक और जिम्मेदारी होगी। वह किसानों को प्रशिक्षण और सहयोग भी देगा। साथ ही उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाले फायदों को भी सुनिश्चित करेगा।

वैसे देखें तो मध्य वर्ग को केंद्र सरकार ने इन बजट प्रस्तावों के जरिए एक लाख करोड़ रुपए का उपहार दिया है। इसमें 12 लाख 75 हजार रुपए की आमदनी वाले लोगों को जहां टैक्स में 80 हजार रुपए का फायदा हुआ है। आयकर में छूट की मांग अरसे होती रही है। पिछले कई बजट में ऐसी छूट नहीं मिलती थी तो लोग इसे लेकर निराश होते रहते थे। बहरहाल 16 लाख रुपए की आमदनी वाले लोगों को टैक्स में 50 हजार रुपए का फायदा हुआ है तो 18 लाख रुपए की आमदनी वाले को टैक्स में 70 हजार रुपए का लाभ दिख रहा है। इसी तरह 20 लाख रुपए की आमदनी वाले को 90 हजार रुपए का फायदा होगा तो 25 लाख रुपए की आमदनी वाले को एक लाख दस हजार रुपए का नए टैक्स नियमों से फायदा होगा। इसी तरह 50 लाख रुपए की आमदनी वाले को भी एक लाख दस हजार रुपए का फायदा हो रहा है। जाहिर है कि मध्य वर्ग को इससे फायदा होता नजर आ रहा है। वायस ऑफ बैंकिंग के प्रमुख अश्विनी राणा के अनुसार, टैक्स बचने से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आयेगा। इससे लोगों की खरीद क्षमता बढ़ेगी। इससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।केन्द्रीय बजट में कृषि और महिलाओं पर भी फोकस किया गया है। पीएम धन-धान्य योजना का प्रस्ताव किया गया है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख किया गया। इससे किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए लाभ होगा। भारतीय पोस्ट यानी इंडियन पोस्ट के दफ्तरों के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसका लाभ भी किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा। एमएसएमई को राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा और नए वर्गीकरण तथा ऋण में भी बढ़ोतरी से लाभ होगा। एमएसएमई को भी क्रेडिट कार्ड देने की तैयारी है। इसके साथ ही बजट प्रस्तावों में राज्यों को शहरों में पूंजीगत योजनाओं में निवेश के लिए ऋण से जहां विकास होगा वहीं रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही, सक्षम आंगनवाड़ी 2.0 के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। ऊर्जा और जल मिशन पर भी फोकस किया गया है। रोजगार पैदा करने के लिए पर्यटन केंद्रों और आध्यात्मिक स्थलों का विकास अच्छा प्रयास है। सरकार ने इसी तरह बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को 75 से 100 प्रतिशत करने की तैयारी है। इससे बीमा क्षेत्र में विकास की उम्मीद है। अश्विनी राणा का कहना है कि इसके बावजूद सरकार को सचेत रहना होगा और बीमा कंपनियों को जनता को लूटने से बचाना होगा। सरकार को इसके लिए कड़ी निगरानी रखनी होगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए नए कोड की घोषणा शीघ्र होगी। जीवन रक्षक दवाइयों पर आयात शुल्क समाप्त करने से रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। हर जिले में कैंसर के इलाज की सुविधा देना भी बड़ा फैसला है। इसके साथ ही मेडिकल पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी है।

आम आदमी का सपना है अपने सिर पर अपना छत होना। इस बजट के जरिए लोगों को घर खरीदने में राहत का भी ऐलान किया गया है। इससे लोगों के साथ ही रियल एस्टेट को भी फायदा होगा। जिससे निर्माण क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बिहार का पटना हवाई अड्डा इन दिनों बेहद व्यस्त है। लेकिन वह छोटा पड़ रहा है। इसके विकास और उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए भी बजट प्रस्ताव किया गया है। इससे देश-विदेश में काम कर रहे बिहार के लोगों को सीधे फायदा होगा और उनकी अपनी माटी से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके साथ ही, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, और उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है।

इस संस्थान के जरिए समूचे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को मजबूती देने की तैयारी है। इसके द्वारा किसानों के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने की तैयारी तो है ही, उनकी आय में बढ़ोत्तरी का भी प्रस्ताव है।

निर्मला सीतारमण के अनुसार, इस संस्थान के जरिए युवाओं को हुनरमंद बनाने की तैयारी है। इसके साथ ही उन्हें उद्यमिता और रोजगार प्राप्त करने के अवसर पैदा करेगा। बिहार में नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे। इसके जरिए पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को भी आर्थिक सहायता मदद दी जा रही है। इसके जरिए उत्तरी बिहार के 50 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की सहूलियत बढ़ेगी।

इससे मिथिलांचल की कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बजट के जरिए लोक को साधने के साथ ही आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाने की कोशिश है। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि जीएसटी दरों में राहत मिलेगी, मध्य वर्ग को कर्ज मुक्ति मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन कह सकते हैं कि यह बजट कुछ संदर्भों में लोकलुभावन है तो कुछ अर्थों में नहीं। इन अर्थों में यह राजनीतिक भी है और राजनीतिक हित साधने का साधन भी।

जीवन मंत्र

बच्चे की परवरिश में संतुलित रवैया अपनाएं

> व्यक्तित्व विकास के लिए माता-पिता का सुरक्षात्मक घेरा तो जरूरी है, लेकिन एक सीमा तक ही, ताकि व्यक्ति को बचपन में खुद की गलतियों से सीखने का अवसर भी मिल सके।

इन दिनों ऐसी खबरों की भरमार है, जिनमें बड़े-बड़े संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे जीवन के छोटे-मोटे संघर्ष के आगे हार जाते हैं। वे व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में अपने जीवन और रिश्ते में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। व्यक्तित्व विकास के लिए माता-पिता का सुरक्षात्मक घेरा तो जरूरी है, लेकिन एक सीमा तक ही, ताकि व्यक्ति को बचपन में खुद की गलतियों से सीखने का अवसर भी मिल सके। मनस्थली की संस्थापक और वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. ज्योति कपूर बताती हैं, 'माता-पिता का अति सुरक्षात्मक घेरा या ओवर प्रोटेक्टिव परवरिश के लिए प्रचलित शब्द है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। ऐसे माता-पिता यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके बच्चे शारीरिक या भावनात्मक रूप से कभी आहत न हो पाएं। इसके लिए वे बच्चों के लिए जरूरत से पहले ही खुद सारी सुविधा उन्हें मुहैया करा देते हैं। वे हमेशा अपनी निगरानी में बच्चों को रखते हैं। किसी भी तरह का निर्णय लेने या कोई नया काम करने का उन पर प्रतिबंध लगाते हैं। जब ये बच्चे बड़े होते हैं और उन्हें दुनिया का सामना करना पड़ता है, तो उनमें हर

तरह की स्किल का जबरदस्त अभाव होता है। इस परवरिश का बच्चे पर क्या नकरात्मक असर होता है, डॉ. ज्योति कपूर बताती हैं, 'माता-पिता के अति-सुरक्षात्मक घेरे से बच्चों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में जबरदस्त कमी आ जाती है। दुनिया का सामना करने के लिए हर व्यक्ति अपने हुनर का इस्तेमाल करता है। अति-सुरक्षात्मक घेरा यह हुनर विकसित नहीं होने देता है।' इसके कारण व्यक्ति में लचीलेपन और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है।ऐसे बच्चे बड़े होने पर बहुत अधिक भावुक हो जाते हैं। उनसे यदि कोई काम नहीं हो पाता है, तो उन्हें अवसाद होने लगता है। वे या तो उग्र व्यवहार करने लगते हैं या फिर उदासीन हो जाते हैं।इस तरह के बच्चों में ना सुनने की आदत विकसित नहीं हो पाती है। इससे उन्हें बहुत अधिक असुरक्षा का भाव होता है। वे ऐसा चाहते हैं कि दूसरे लोग हमेशा उन्हें पसंद करें।

अत्यधिक सुरक्षात्मक माता-पिता के बच्चे अपने पूरे जीवन में दबाव में रहते हैं। बड़े होने पर वे डरपोक, निर्णय लेने में असमर्थ व्यक्ति बन जाते हैं।पहले कदम से लेकर पहला स्कूल डांस तक, आपका बच्चा जीवन में ढेर सारी नई चीजें आजमाएगा। आपको उन्हें कुछ नया और रोमांचक करने के इन पहले अवसरों से डराना नहीं चाहिए। सुरक्षा का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन अपने मन से डर को निकाल दें और बच्चे को नई-नई चीजें और अनुभव आजमाने दें।

शख्सियत — अमृत कौर

स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता

राजकुमारी डेम बीबीजी अमृत कौर एक भारतीय कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थीं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ उनके लंबे समय तक जुड़ाव के बाद, उन्हें 1947 में भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। 1957 तक वह इस पद पर रहीं। उन्होंने खेल मंत्री और शहरी विकास मंत्री का भी कार्यभार संभाला और राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1887 को बादशाह बाग, लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (तब उत्तर-पश्चिमी प्रांत), भारत में हुआ था। कौर का जन्म कपूरथला के राजा रणधीर सिंह के छोटे बेटे राजा सर हरनाम सिंह अहलूवालिया से हुआ था। अपने कार्यकाल के दौरान, कौर ने भारत में कई स्वास्थ्य देखभाल सुधारों की शुरुआत की। इस क्षेत्र में उनके योगदान और महिलाओं के अधिकारों की वकालत के लिए उन्हें व्यापक रूप से याद किया जाता है। कौर भारत की संविधान सभा की सदस्य भी थीं, जिसने भारत का संविधान तैयार किया था। इंग्लैंड से भारत लौटने के बाद, कौर को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में रुचि हो गई। उनके पिता का गोपाल कृष्ण गोखले सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध था, जो अक्सर उनसे मिलने आते थे। कौर महात्मा गांधी के विचारों और दृष्टिकोण से आकर्षित थीं, जिनसे उनकी मुलाकात 1919 में बॉम्बे (मुंबई) में हुई थी। कौर ने 16 वर्षों तक गांधी के सचिव के रूप में काम किया, और उनके पत्राचार को बाद में लेटर्स टू राजकुमारी अमृत कौर नामक पत्रों की एक श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किया गया था। राजकुमारी अमृत कौर ने कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नई दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत सरकार ने उनके सम्मान में कॉलेज का नाम बदलकर राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर दिया। 1957 से 1964 में अपनी मृत्यु तक वह राज्यसभा की सदस्य रहीं।

1958 और 1963 के बीच कौर दिल्ली में अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। अपनी मृत्यु तक, वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय तपेदिक एसोसिएशन और सेंट जॉन एम्बुलेंस कोर की अध्यक्षता करती रहीं। उन्हें रेने सैंड मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें 1947 में टाइम मैगज़ीन की वुमन ऑफ़ द ईयर नामित किया गया था। 6 फ़रवरी 1964 में उनका निधन हो गया।

जीवन ऊर्जा

आयन रैंड : जन्म- 2 फरवरी 1905 — जन्म

अपने आप को महत्व देना सीखें

> आयन रैंड का जन्म 2 फरवरी 1905 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। छह वर्ष की उम्र में खुद ही पढ़ना सीख लेने के दो साल बाद उन्हें बच्चों की एक फ्रांसीसी मैगजीन में अपना पहला काल्पनिक (फिक्शनल) हीरो मिल गया। हीरो की एक ऐसी छवि जो ताउम्र उनके दिलो-दिमाग पर चस्पां रही। हर साल इनकी किताबों की हजारों प्रतियां बिकती हैं। अब तक उनकी किताबों की कुल 2.5 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं। आयन रैंड की 6 मार्च, 1982 को न्यूयॉर्क शहर में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई।

जो भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो आज भी भविष्य में ही जी रहा है। सभी को अपने निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी को भी अपने निर्णय दूसरों पर थोपने का अधिकार नहीं है। बुराई और अच्छाई में अगर कोई समझौता होता है तो फायदा हमेशा बुराई का ही होगा। आदमी की सोचने की क्षमता का ही उत्पाद है धन। महान लोगों पर कभी भी शासन नहीं किया जा सकता है। भ्रष्ट किस्म के लोगों के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आप अपना काम कितना अच्छी तरह से करते है, इसके अलावा किसी बात की कोई अहमियत नहीं है। तर्कसंगत व्यक्ति अपनी सोच और समझ के अनुसार आगे बढ़ता है। भावनाओं और अरमानों के जरिए नहीं। सच्चाई से तो बचा जा सकता है, लेकिन सच्चाई से दूर भागने के नतीजों से कभी बचा नहीं जा सकता है। समाज के गुणों को नापने का यंत्र है पैसा।

अगर कोई कुछ करने के लायक है तो वह ज्यादा करने के लायक है। अपर-क्लास देश का भविष्य है तो मिडिल-क्लास देश का भूतकाल। रचनात्मक व्यक्ति कुछ कर दिखाने की चाह से प्रेरित होते है ना की दूसरों को गिराने की चाह से।

हर मुद्दे के दो पहलु होते है, एक सही और दूसरा गलत, लेकिन बीच में हमेशा बुराई ही रहती है। कुछ भी पाने के लिए विचार की जरूरत होती है। आपको पता होना चाहिए की आप क्या कर रहे है। फिलोसोफी का ही पुरातन रूप है धर्म। खुद की कद्र करना सीखिए, मतलब यह भी है की अपनी खुशी के लिए लड़ाई कीजिए। आपको लगता है कि हर बुराई का जड़ पैसा है। कभी यह जाना है की इस पैसे की जड़ कहां है? बिना शर्त की इच्छा रखने वाले जल्दी भरोसा कायम कर लेते है। ज्यादा बोलने से कहीं बेहतर है ज्यादा सुनना। अन्तर्मुखी होना किसी की सफलता की राह का रोड़ा नहीं है। सफलता का पहला इशारा है आलोचना। मौकों की सीढियों पर कदम रखकर ही सफलता की सीढ़ी को सबसे अच्छे तरीके से चढ़ते हैं।

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्य प्रदेश

हमारा नजरिया ही जिंदगी की दशा और दिशा तय करता है

एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे। इनमें से दो बच्चों गुर्वित और तन्विक में गहरी दोस्ती थी। ये दोनों ही बच्चे गुरुकुल के सबसे होशियार बच्चे थे। एक दिन उस गुरुकुल में उनके आचार्य दोनों को घुमाने बाहर ले गए। घूमते हुए वो तीनों एक खूबसूरत बाग में पहुँच गए। वह तीनों वहां आस पास की प्राकृतिक शोभा का आनंद ले रहे थे। तभी उन लोगों की नज़र आम के एक पेड़ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वहां एक बालक डंडा लेकर आया और पेड़ के तने पर डंडा मारकर फल तोड़ने लगा। आचार्य ने अपने साथ आये दोनों बच्चों से आम के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए पूछा क्या तुम दोनों ने यह दृश्य देखा। हाँ गुरुदेव हमने उस बालक को डंडा मारकर आम का फल तोड़ते हुए देखा, बच्चों ने उत्तर दिया।

पंडित कैलाशचंद्र शर्मा
वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक।
मो. नं. 9425980556

गुरु ने उनमें से एक बच्चे से पुछा-इस दृश्य के बारे में तुम्हारी क्या राय है?

उस बच्चे ने जवाब दिया गुरुदेव मैंने देखा कि कैसे उस बालक को डंडा मारकर आम के पेड़ से फल तोड़ना पड़ा। मैं सोच रहा हूँ कि जब वृक्ष भी बगैर डंडा खाए फल नहीं देता तब किसी मनुष्य से कैसे काम निकाला जा सकता है। यह दृश्य हमें एक महत्वपूर्ण सामाजिक सत्य का आइना दिखा रहा है कि यह दुनिया राजी खुशी नहीं मानने वाली है। यहाँ दबाव डालकर ही समाज या लोगों से कोई काम निकाला जा सकता है।

गुरु ने अब दूसरे बच्चे से पूछा तुमने भी डंडा मारकर फल तोड़ने वाला यह दृश्य देखा तो तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? दूसरा बच्चा बोला गुरू जी यह दृश्य देखकर मुझे कुछ और ही लग रहा है जिस प्रकार आम का यह पेड़ डंडे खाकर भी उस बालक को मधुर आम दे रहा है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी स्वयं दुःख सहकर भी दूसरों को हमेशा सुख देना चाहिए। कोई अगर हमारा अपमान भी करे तो बदले में हमें उसका उपकार करना चाहिए। यही सज्जन व्यक्तियों का धर्म है। यह कहकर वो गुरूदेव का चेहरा देखने लगा। गुरुदेव मुस्कुराये और बोले-देखो बच्चों जीवन में दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। अभी-अभी तुम्हारे सामने घटना एक ही घटी, लेकिन तुम दोनो ने उसे अलग-अलग रूप में ग्रहण किया, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में भिन्नता है।

मनुष्य अपनी दृष्टि के अनुसार ही जीवन के किसी प्रसंग की व्याख्या करता है। उसी के अनुरूप कार्य करता है और यूं कहे कि उसी के मुताबिक फल भी भोगता है। गुरु ने पहले बच्चे से कहा तुम सब कुछ अधिकार से डराकर हासिल करना चाहते हो, वहीं तुम्हारा मित्र प्रेम से पाना चाहता है। अगर हम इस कहानी में सिर्फ घटना को देखने के नज़रिए पर फोकस करें तो आप यकीन मानिये परिस्थितियों को देखने का हमारा नजरिया ही हमारी ज़िन्दगी की दशा और दिशा तय कर सकता है। आप अपने आसपास ढूंढेंगे तो आप को कुछ लोग ऐसे जरूर नज़र आ जायेंगे। जो हमेशा खुश दिखाई देते हैं। ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि उनके जीवन में सिर्फ खुशियाँ और सफलता ही है। इसलिए वो हर पल खुश नज़र आते हैं। उनके जीवन में भी दुःख तकलीफ़ असफलता चिंता तनाव है, लेकिन उनका इन्हें देखने का नजरिया सकारात्मक है। इनसे निपटने का तरीका सकारात्मक है। अब इन मुसीबतों से निपटा नहीं जा सकता, क्योंकि जिन कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग सकारात्मक बने रहते हैं वहीँ कई लोग नकारात्मकता को अपना लेते हैं और फिर चिंता तनाव में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं।

अपने विचार

ये बजट, देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगा, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे... ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

गोली के घाव पर बैंड एड. वैश्विक अनिश्चितता के बीच, हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए बड़े बदलाव की आवश्यकता थी। लेकिन यह सरकार विचारों के मामले में दिवालिया हो चुकी है।

-राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

यह बजट युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाला और विकसित युवा-विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने वाला साबित होगा।

-योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री,उप्र

महाकुंभ भगदड़ में जान गंवाने वालों की संख्या बजटीय आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

-अखिलेश यादव, सपा प्रमुख

अपने विचार

डीबीडी कार्यालय
ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के. के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001
indiagroundreport@gmail.com
भेज सकते हैं।

यह अखबार "माध्यम कार्पोरेट सर्विसेज लि. " के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक अरुणलाल द्वारा ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के. के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 से प्रकाशित एवं सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, एन.के.इंडस्ट्रियल इस्टेट, इनसाइड प्रवासी इंडिस्ट्रयल इस्टेट गेट नं. 2, गोरेगांव पू., मुंबई-63 से मुद्रित। फोन नं. 022-66555719 ईमेल : indiagroundreport@gmail.com कार्यकारी संपादक : अमित बृज (पी.आर.बी. अधिनियम के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार)।

कहीं बंटी मिठाइयां तो कहीं चले शब्द बाण

देश के बजट पर खुलकर बोले महाराष्ट्र के मिनिस्टर्स

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार 1 फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। आम बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। अब 16 से 20 लाख रुपये की सालाना कमाई पर 20% टैक्स, 20 से 24 लाख रुपये की कमाई पर 25% टैक्स और 24 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। इसके अलावा, अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है, जिससे करदाताओं को अपने पुराने रिटर्न सुधारने का ज्यादा मौका मिलेगा। सीनियर सिटीजंस के लिए भी राहत भरी खबर है। अब ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, स्टार्टअप्स को टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 5 साल और बढ़ा दी गई है और भी कई बदलाव इस वर्ष के बजट में देखने को मिले। बजट पेश होने के दौरान नासिक जिले के विभिन्न राजनीतिक नेताओं और सामान्य वर्ग ने नवभारत को अपनी प्रतिक्रिया दी। जिन में सांसद, विधायकों के साथ पार्टियों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बजट से सत्ताधारी खुश हैं तो वहीं विरोधी पार्टियों में नाराजगी देखी जा रही है।

सर्वांगीण विकास को बढ़ावा

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के विकास को गति देने वाला बजट पेश किया, जिसमें देश के गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। 12 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त करने के ऐतिहासिक फैसले से देश के आम मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है।

छगन भुजबल, पूर्व उपमुख्यमंत्री

निराशाजनक बजट

यह बहुत निराशाजनक बजट है। किसानों के लिए प्रावधान बहुत कम किए गए हैं। कृषि उपकरणों, बीजों और कृषि रसायनों पर जीएसटी है, लेकिन इसे कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। जब प्याज, कपास और अनाज के लिए गारंटीकृत मूल्य प्रदान करने की आवश्यकता थी, तब कुछ भी नहीं किया गया।

डॉ। शोभा बच्छाव, सांसद, धुलिया

उम्मीदें पूरी नहीं हुईं

दरअसल, विकसित भारत की घोषणा के बाद यह पहला बजट है, इसलिए उम्मीद थी कि इसमें देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले किसानों और मध्यम वर्ग के लिए टिकाऊ और सकारात्मक पहलू होंगे। अर्थ संकल्प के माध्यम से जन-हितैषी घोषणाओं का आभास पैदा किया गया।

सांसद राजाभाऊ वाजे, नासिक

आम लोगों को धोखा

बजट में आम नागरिकों और किसानों की चिंताओं को नजरअंदाज किया गया है जो वित्तीय संकट में हैं। कर्मचारियों को भी गहरी निराशा हुई है और बजट बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह विकास का गुब्बार दिखाकर आम जनता को आश्वस्त करने का एक खुला प्रयास है।

सांसद भास्कर भागरे, पेठ-दिंडोरी

अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी

बजट के माध्यम से अनेक महत्वाकांक्षी निर्णय लिए गए हैं तथा समाज के सभी वर्गों को सहायता प्रदान की गई है। मध्यम वर्ग और धनाढ्य वर्ग को 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करके खुशखबरी दी गई है। आज के केन्द्रीय बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों और पिछड़े वर्गों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, वे स्वागत योग्य हैं।

दादा भुसे, पूर्व पालकमंत्री

अर्थव्यवस्था को गति

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग के लिए एक स्वप्निल बजट पेश किया। मध्यम वर्ग को 12 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त करके बड़ी राहत प्रदान की गई है। यह बजट विकसित भारत के लिए एक ऐतिहासिक बजट है, जो विकसित भारत की ओर अग्रसर है। यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट है।

सीमा हिरे, विधायक, नासिक पश्चिम

व्यापक बजट

यह आम लोगों को राहत और संतुष्टि देने वाला बजट है। सामान्य और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है क्योंकि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं है। जो महिलाएं उद्यमी बनना चाहती हैं और देश की प्रगति के लिए काम करना चाहती हैं, उन्हें 2 करोड़ रुपये का टर्म लोन मिलेगा। यह सभी क्षेत्रों के विकास के लिए एक सर्वसमावेशी बजट है।

विधायक राहुल ढिकले, नासिक पूर्व

आम लोगों की निराशा

यह ऐसा बजट है जो एक हाथ से देता है और दोनों हाथों से लेता है। इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। यद्यपि कर में छूट दी जाती है, फिर भी कितने सामान्य नागरिकों की आय 12 लाख रुपये है? इस पर विचार किया जाना चाहिए था। ऐसा प्रतीत होता है कि बजट में मुद्रास्फीति कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।

सुधाकर बडगुजर, जिला प्रमुख ठाकरे गुट

ग्रामीण भारत की सूरत बदलने वाला बजट : मुख्यमंत्री फडणवीस

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने ऐतिहासिक और समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए लाभकारी होगा और नागरिक-केंद्रित निवेश को बढ़ावा देगा।

मध्यम वर्ग, युवाओं और किसानों को मिलेगी राहत

फडणवीस ने कहा कि यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। आयकर सीमा बढ़ाने से 12 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त किया गया, जिससे मध्यम वर्ग और वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इस फैसले से बाजार में मांग और उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

कृषि क्षेत्र को मिलेगा प्रोत्साहन

इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए विशेष घोषणाएं की गई हैं। 100 जिलों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं, तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति और मछुआरों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को नया जीवनदान मिलेगा और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा।

एमएसएमई और स्टार्टअप को मिलेगा समर्थन

एमएसएमई और युवा उद्यमियों के लिए ऋण सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। विशेष रूप से महाराष्ट्र में स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ रुपये की ऋण सीमा का प्रावधान किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

नई बुनियादी ढांचा नीति और पीपीपी परियोजनाओं का महत्व

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना से महाराष्ट्र को विशेष लाभ मिलेगा। इसके तहत निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ेगा, जो रोजगार सृजन में सहायक होगा।

महाराष्ट्र के लिए बजट में खास प्रावधान

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं:

- ग्रामीण संपर्क सुधार परियोजना के लिए 683 करोड़ रुपये
- कृषि व्यवसाय परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये
- आर्थिक क्लस्टर के लिए 186 करोड़ रुपये
- उपसा सिंचाई योजनाओं के लिए 186 करोड़ रुपये
- फडणवीस ने इस बजट को राज्य के समग्र विकास और प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया
- और आशा व्यक्त की कि इससे महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी।

महावितरण की 'गो-ग्रीन' पहल को जबरदस्त प्रतिक्रिया

कल्याण-भांडुप में 1 लाख उपभोक्ता सालाना बचा रहे 1.25 करोड़ रुपये

डीबीडी संवाददाता | कल्याण/मुंबई

कल्याण और भांडुप अंचल में 1 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं ने महावितरण की 'गो-ग्रीन' पहल में भाग लेकर मुद्रित बिजली बिल को अलविदा कह दिया है। इससे उपभोक्ताओं को सालाना करीब 1.25 करोड़ रुपये की बचत हो रही है।

कैसे हो रही है बचत?

महावितरण की योजना के तहत उपभोक्ताओं को ईमेल और एसएमएस के जरिए बिजली बिल प्राप्त करने पर प्रति माह 10 रुपये की छूट मिलती है। इस तरह सालाना 120 रुपये की बचत होती है। कल्याण सर्कल में 52,129 और भांडुप सर्कल में 49,856 उपभोक्ता इस योजना से जुड़े हैं।

स्मार्ट बिलिंग का लाभ

गो-ग्रीन पहल के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बिजली बिल, भुगतान रसीद और पिछले बिलों की जानकारी महावितरण के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध है। इससे बिल का ऑनलाइन भुगतान भी सरल और तेज हो गया है। महावितरण ने नए साल के उपहार के रूप में गो-ग्रीन सेवा चुनने पर उपभोक्ताओं को 120 रुपये की एकमुश्त छूट देने की घोषणा की है।

वाशी मंडल में सबसे ज्यादा पंजीकरण

गो-ग्रीन पहल में वाशी मंडल सबसे आगे है, जहां 22,436 उपभोक्ताओं ने इस पहल को अपनाया है। इसके बाद ठाणे शहर, कल्याण-1, वसई, कल्याण-2, पेण और पालघर मंडल भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। महावितरण ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस पर्यावरण अनुकूल पहल में भाग लेकर न केवल पैसे बचाएं, बल्कि प्रकृति संरक्षण में भी योगदान दें।

महिला IPS अधिकारी के पति पर 25 करोड़ की ठगी का आरोप

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

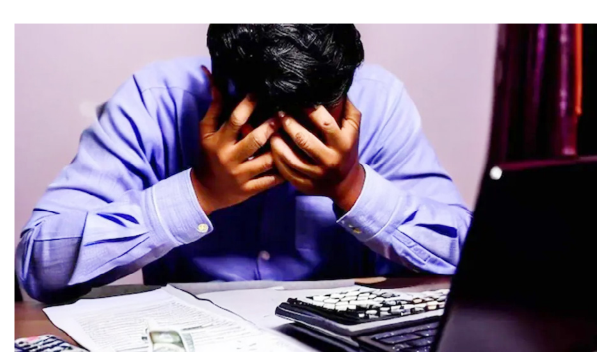

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने एक आईपीएस अधिकारी के पति पुरषोत्तम चव्हाण और अन्य के खिलाफ सरकारी कोटे के फ्लैट कम कीमत पर देने के नाम पर 25 करोड़ रुपये की ठगी के मामला में दर्ज किया है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी पुरषोत्तम चव्हाण पहले से ही एक अन्य मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्त में हैं। अब उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी दफ्तरों में अपने संपर्कों का हवाला देकर मुंबई के प्रभादेवी, दादर, परेल, ठाणे और पुणे में सरकारी कोटे के फ्लैट और प्लॉट कम दामों में दिलाने का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपये ऐंठ लिए। चव्हाण के अलावा इस मामले में उनके कुछ साथियों, परेल-शिवड़ी स्टांप रजिस्ट्रेशन कार्यालय के एक सहायक और अन्य अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। इन पर फर्जी बिक्री दस्तावेज तैयार करने में मदद करने का आरोप है। केदार डेगवेकर (57) नाम के एक कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि जुलाई 2020 में चव्हाण ने उन्हें उनकी पत्नी के आधिकारिक निवास, जो कोलाबा पुलिस स्टेशन के ऊपर स्थित है, बुलाया था। वहां उन्होंने खुद को सरकारी अधिकारी बताने वाले कुछ लोगों की मौजूदगी में डेगवेकर से एक बिक्री अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए और 3।37 करोड़ रुपये ले लिए। हालांकि, उन्हें अब तक वह तीन बीएचके फ्लैट नहीं मिला, जिसका वादा किया गया था। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है।

राशिफल

प्रियंका जैन

मेष: योजना फलीभूत होगी। मनमाफिक स्थानांतरण या पदोन्नति हो सकती है। कार्यस्थल पर सुधार होगा। सामाजिक कार्य करने की इच्छा रहेगी। मान-सम्मान मिलेगा। घर-परिवार की चिंता रहेगी।

वृष: डूबी हुई रकम प्राप्त होने के योग हैं। यात्रा लाभदायक रहेगी। आय में वृद्धि होगी। व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल रहेगा। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में चैन रहेगा। कोई बुरी खबर मिल सकती है।

मिथुन: ऐश्वर्य के साधनों पर बड़ा खर्च हो सकता है। भूमि व भवन आदि के कार्य मनोनुकूल रहेंगे। परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। नौकरी में चैन रहेगा। शत्रु पस्त होंगे।

कर्क: फालतू खर्च होगा। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। धन की तंगी होगी। बेकार बातों पर ध्यान न दें। विचारों की स्पष्टता न होने से उलझनें रहेंगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। नौकरी में स्थानांतरण या परिवर्तन संभव है।

सिंह: प्रियजनों के साथ बेवजह रिश्तों में खटास आ सकती है। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी। हताशा का अनुभव होगा। मन की बात किसी को न बतलाएं। संवेदनशीलता बढ़ेगी। लेन-देन में जल्दबाजी न करें।

कन्या: पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। शैक्षणिक व शोध कार्य मनोनुकूल रहेंगे। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उत्साह व प्रसन्नता में वृद्धि होगी। नौकरी में कोई नया कार्य कर पाएंगे। अधिकारी प्रसन्न

तुला: नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। मेहनत का फल प्राप्त होगा। अपेक्षित कार्य समय पर पूरे होंगे। मित्रों का सहयोग कर पाएंगे। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। सुख के साधन जुटेंगे। कारोबारी लाभ बढ़ेगा। शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड मनोनुकूल लाभ देंगे।

वृश्चिक: दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। शेयर मार्केट से आशातीत लाभ होगा। नौकरी में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। राजकीय बाधा दूर होगी। तनाव व चिंता में कमी होगी।

धनु: चोट व दुर्घटना से शारीरिक हानि की संभावना है। दुष्टजनों से दूरी बनाए रखें। बिना वजह कहासुनी हो सकती है। चिंता तथा तनाव रहेंगे। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। यात्रा यथासंभव टालें। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। धैर्य रखें।

मकर: राजकीय सहयोग प्राप्त होगा। कोई रुका काम बन सकता है। तीर्थयात्रा की योजना बनेगी। तंत्र-मंत्र में रुचि जागृत होगी। सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। कारोबार लाभदायक रहेगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। प्रतिद्वंद्वी शांत रहेंगे। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें।

कुंभ: आत्मसम्मान बना रहेगा। अच्छी खबर प्राप्त होगी। कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा। मान-सम्मान मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। घर-बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी। भूले-बिसरे साथी तथा रिश्तेदारों से मुलाकात होगी।

मीन: भेंट व उपहार की प्राप्ति होगी। यात्रा लाभदायक रहेगी। रोजगार में वृद्धि होगी। कोई बड़ा काम होने से प्रसन्नता रहेगी। समय की अनुकूलता का लाभ लें। कारोबारी लाभ बढ़ेगा। नौकरी में उच्चाधिकारी की प्रसन्नता प्राप्त होगी।

शेयर मार्किट से लाभ के ग्रहयोग

प्रियंका जैन
9769994439

आज के समय में शेयर मार्किट एकऐसा विषय है जिसकी और हर एकव्यक्ति आकर्षित होता है और इसे धनलाभ अर्जित करने के लिए एक सुनहरेमार्ग के रूप में देखा जाने लगा है औरअधिकांश व्यक्ति अपने पास उपस्थितधन का कुछ ना कुछ भाग शेयर मार्किटमें इन्वेस्ट करने के इच्छुक होते ही हैं, पर सभी व्यक्तियों को इस क्षेत्र से लाभप्राप्त होता ही हो ऐसा नहीं है, जहाँबहुत से लोग शेयर में अपना धनइन्वेस्ट करके बड़ा लाभ कमाते हैं तोबहुत से व्यक्तियों को भारी नुकसानका भी सामना करना पड़ता है ज्योतिषीय दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति की जन्मकुंडली में ग्रहस्थिति भिन्न-भिन्न होती है इसलिए जिस कार्य में एक व्यक्ति उन्नति कर रहा है दूसरा भी उसमे सफल हो ऐसा आवश्यक नहीं है इसी प्रकार शेयर मार्किट का क्षेत्र किसी व्यक्ति के लिए लाभदायक होगा या नहीं यह पूरी तरह उसकी कुंडली में बनी ग्रहस्थिति पर निर्भर करता है, तो आईये जानते हैं हमारी कुंडली में कौनसे ग्रहयोग शेयर मार्किट से लाभ कराने में अपनी भूमिका निभाते हैं।

ज्योतिष में शेयर मार्किट के लिए सीधेसीधे किसी एक ग्रह की भूमिका नहोकर कुंडली के "पंचम भाव" कोसर्वाधिक महत्व दिया गया है, जन्मकुंडली के पंचम भाव को शेयर, लॉट्री या स्पेकुलेशन आदि का कारकभाव माना गया है इसलिए शेयरमार्किट से जुड़ने या लाभ प्राप्त करने मेंसबसे पहले तो कुंडली के पंचम भावऔर पंचमेश का शुभ स्थिति में होनाआवश्यक है, इसके बाद लाभ स्थानअर्थात कुंडली के ग्यारहवे भाव की भीयहाँ महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकिकिसी भी प्रकार से इन्वेस्ट किये गएधन से आपको लाभ प्राप्त हो पायेगा यानहीं या किस स्तर का लाभ जीवन मेंहोगा यह लाभ स्थान और लाभेश कीस्थिति पर निर्भर करता है, शुक्र धनऔर विलासिता का कारक होने से यहाँअपनी सहायक भूमिका निभाता है इसीप्रकार राहु को आकस्मिक कार्य याझटके के कार्यों का कारक होने से राहुकी भी यहाँ सहायक भूमिका होती है, अतः निष्कर्षतः कुंडली में पंचम भावऔर पंचमेश बली स्थिति में होने परशेयर-मार्केट से शुभ परिणाम प्राप्तहोते हैं इसके अलावा लाभ स्थान, लाभेश और शुक्र जितनी अच्छी औरमजबूत स्थिति में होंगे उतना ही अच्छीमात्रा में व्यक्ति को लाभ होता है।

बजट से झामुमो निराश

झारखंड को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया : मनोज पांडेय

रांची। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारण के बजट 2025 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने निराशा जतायी है। झामुमो ने कहा है कि इस बजट में झारखंड को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। झामुमो ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में झारखंड के लिए कुछ भी नहीं है। सत्तारूढ़ दल ने आरोप लगाया कि निर्मला सीतारमण के बजट में राज्य और इसके लोगों को 'पूरी तरह से नजरअंदाज' किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी 2025) को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया।

मनोज पांडेय बोले- बजट में झारखंड के लिए कुछ भी नहीं

बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा, 'बजट में झारखंड के लिए कुछ भी प्रस्तावित नहीं किया गया है। पड़ोसी राज्य बिहार को कई परियोजनाएं दी गयी हैं, लेकिन झारखंड और उसके लोगों की पूरी तरह उपेक्षा की गयी है।' झामुमो नेता ने आरोप लगाया कि झारखंड के खनिज देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन राज्य के साथ 'सौतेला व्यवहार' किया गया है।

एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड, फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट, पटना IIT, हवाई अड्डे का भी विस्तार

बजट में बिहार के लिए छप्पर फाड़ ऐलान

एजेंसी | पटना

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बजट (2025-26) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के लिए छप्परफाड़ ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने राज्य के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया है, पटना एयरपोर्ट का विस्तार करने की घोषणा की है, पटना आईआईटी को और भी बड़ा किया जाएगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने आईं तो उनके पोशाक से ही संकेत मिल गया था कि बिहार को कुछ बंपर मिलने वाला है। वित्त मंत्री ने जो साड़ी पहनी थी पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित हस्तकला विशेषज्ञ दुलारी देवी ने बुना था। इस साड़ी में मधुबनी पेंटिंग की झलक देखने को मिल रही थी।

मखाना बोर्ड का गठन

वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना की खेती कर रहे किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। मखाना बोर्ड के गठन से बिहार के किसानों को मखाने की खेती में मदद मिलेगी। इससे उनकी आय बढ़ बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस कार्य में लगे लोगों को FPO के रूप में संगठित किया जाएगा। बोर्ड मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेगा कि उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। बता दें कि बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सीतामढ़ी जिलों में मखाना की पैदावार की जाती है।

बिहार को मिलेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में एयरपोर्ट सेवाओं में विस्तार करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि उडान स्कीम के तहत देश के 120 नए स्थानों को एयरसेवा से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री बिहार में विमान सेवाओं के विस्तार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने पटना एयरपोर्ट की क्षमता में व्यापक विस्तार करने की घोषणा की है। इसके अलावा बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। जेडीयू ने केंद्र सरकार से बिहार में एयरपोर्ट की मांग की थी।

IIT पटना की क्षमता का होगा विस्तार

बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि आईआईटी की क्षमता विस्तार करने की दिशा में पटना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके तहत देश में पांच आईआईटी में अतिरिक्त 6,500 छात्रों को समायोजित करने के लिए बुनियादी ढांचे को जोड़ना शामिल है।

फूड प्रोसेसिंग संस्थान की स्थापना

वित्त मंत्री बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, ₹'पूर्वोदय' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, हम बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना करेंगे। यह संस्थान पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देगा।

मिथिलांचल में वेस्टर्न कोशी कैनाल प्रोजेक्ट

लगातार बाढ़ की विभीषिका झेलते रहने वाले बिहार के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहम ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा।

'केंद्र का बजट या बिहार का?'

विपक्ष ने सरकार पर अन्य राज्यों की अनदेखी का लगाया आरोप

बजट में बिहार को खास तवज्जो देने के लिए विपक्ष केंद्र पर तंज कसा है। विपक्ष ने केंद्र इस साल के केंद्रीय बजट में बिहार के अलावा अन्य राज्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा, 'मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह भारत सरकार का बजट था या यह बिहार सरकार का बजट था? क्या आपने केंद्रीय वित्त मंत्री के पूरे बजटीय भाषण में बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य का नाम सुना?' आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार बैसाखी पर है। इस बैसाखी को बरकरार रखने के लिए सरकार ने अन्य राज्यों के विकास हित की अनदेखी की। आगे जब उनसे बजट में कर छूट की घोषणाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कर प्रस्तावों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना होगा। वित्त मंत्री ने कुछ दावे किए हैं; उन दावों पर गौर करना होगा।

केंद्र सरकार का राज्यों को तोहफा

50 साल के लिए मिलेगा 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। सरकार राज्यों को 50 साल के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त कर्ज देगी। ये पैसा सीधे सड़कों, पुलों, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे में खर्च होगा, जिससे विकास की गाड़ी और तेज दौड़ेगी।

शहरों को मिलेगा अर्बन चैलेंज फंड

सीतारमण ने शहरों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड भी लॉन्च किया है। इस फंड से शहरों को पानी, साफ-सफाई और रचनात्मक प्रोजेक्ट्स में निवेश का मौका मिलेगा, ताकि वे सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि विकास के हब बन सकें। यह फंड राज्यों को नए और अनोखे प्रोजेक्ट्स अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। इसके तहत शहरों में प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ विकास के मॉडल बनाए जाएंगे, जिससे वहां रहना और बेहतर हो जाएगा।

हर मंत्रालय लाएगा पीपीपी प्रोजेक्ट्स की योजना

हर मंत्रालय अगले तीन साल के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) प्रोजेक्ट्स की योजना बनाएगा। इसके साथ ही 10 लाख करोड़ रुपये जुटाने के लिए दूसरा एसेट मोनेटाइजेशन प्लान भी शुरू किया गया है।

नए प्रोजेक्ट्स में होगा पैसा पुनर्निवेश

एसेट मोनेटाइजेशन से जो पैसा आएगा, उसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा ताकि विकास की रफ्तार धीमी न हो।

सरकार देगी 25% फंडिंग

जो प्रोजेक्ट बैंक से फंडिंग के लायक होंगे, उनमें सरकार खुद 25% तक की फंडिंग देगी। बाकी का पैसा बॉन्ड, बैंकिंग संस्थाओं और पीपीपी मॉडल से जुटाया जाएगा

यूपी में केंद्रीय बजट पर भिड़े पक्ष-विपक्ष

- सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के हित में बताया
- अखिलेश बोले- बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी महाकुंभ में हुई मौतों की सही संख्या

एजेंसी | लखनऊ

केंद्रीय बजट पर यूपी में राजनीतिक दलों ने अलग-अलग राय जाहिर की है। एक तरफ भाजपा के नेताओं ने जहां बजट की सराहना की है, वहीं, विपक्ष ने निराशा जाहिर की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजट को निराशाजनक बताया है। वहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि महाकुंभ भगदड़ में हुई मौतों की संख्या जानना जरूरी है, न कि बजट के आंकड़ों को जानना।

मोदी सरकार के बजट से यूपी को मिलेगा सबसे अधिक लाभ: योगी

यह आम बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए ठोस कदमों की आधारशिला है। पीएम ने ज्ञान का बजट बताकर चार अक्षरों में इसे प्रभाषित किया है। जी फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। यानि इन चार महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रखकर एक विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले साढ़े दस वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। इस बजट से अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलेगी। राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान देने के लिए जो ब्याज मुक्त लोन देने पर ध्यान दिया गया है, मिडिल क्लास को टैक्स में छूट देने के लिए कदम उठाया गया है यह स्वागत योग्य है। कहा कि मछुवारों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेरी और मत्स्य पालन के लिए पांच लाख का कर्ज, कपास प्रोडक्शन योजना ये अत्यंत लाभकारी साबित होंगे। यह सरकार सर्वमाज और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम कर रही है। अगले पांच वर्ष में पांच लाख महिलाओं और अनसुचित जाति जनजाति को दो करोड़ तक के टर्म लोन देने के लिए एक नई योजना को शुरू करने का जो प्रस्ताव शुरू हो रहा है।

अखिलेश ने महाकुंभ भगदड़ पर घेरा

अखिलेश ने कहा है कि, हमारे लिए आम बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है महाकुंभ में जिन लोगों की जान गई है, वह आंकड़े। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वह झूठे हैं। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है- जो सबसे बड़ी परंपरा का आयोजन नहीं कर पा रहे, वह क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे। आप लोगों को स्नान न करा पाएं, क्या यह विकसित भारत की परिभाषा है?

मायावती ने निराशाजनक बताया

पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है- अगर सरकार का बजट इतना देश हित में है तो आखिर लोगों के जीवन में लगातार तंगहाली और बदहाली क्यों है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है- देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख शांति आदि के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है। जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी। लेकिन भारत सरकार का भी बजट कांग्रेस की तरह राजनीतिक स्वार्थ का अधिक व जन एवं देशहित का कम लगता है। विकसित भारत का सपना बहुजनों के हित का भी होना चाहिए।

कांग्रेस ने कहा- किसी चतुर बनिया ने बनाया बजट

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए बजट 2025 को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि बजट 2025 देखकर लगता है कि किसी चतुर बनिया ने बनाया हो। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि बजट में जिनकी आय 12 लाख,18 लाख 25 लाख तक है, उनको छूट दी गई है , छूट भी उन्हें जो आसानी से टैक्स दे सकते हैं ।र यदि आपकी आय 12 लाख से कम है तो कोई राहत नहीं, अब ऐसे दौर में 12 लाख कौन कमा रहा है, जब बेरोजगारी-मंहगाई चरम पर है, समझ सकते हैं ?

स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की 'फंड ऑफ फंड्स' योजना का ऐलान

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में रिकॉर्ड 8वां केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए उभरते उद्यमियों के वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप के लिए 'फंड ऑफ फंड्स' योजना के एक और दौर का ऐलान किया। वित्त्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट 2025-26 में स्टार्टअप के लिए 'फंड ऑफ फंड्स' योजना की यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार स्टार्टअप के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

1.57 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता

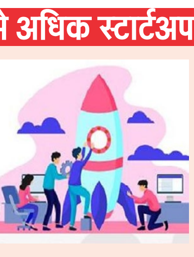

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने अब तक 1.57 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है। स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से सरकार ने इस विकास को पोषित करने और उद्यमियों की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टार्टअप इंडिया की कार्य योजना 16 जनवरी 2016 को पेश की गई थी। केंद्र सरकार उसी वर्ष स्टार्टअप की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के कोष के साथ 'फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स' (एफएफएस) योजना लाई थी। इसकी निगरानी एजेंसी डीपीआईआईटी है, जबकि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एफएफएस के लिए संचालन एजेंसी है।

बजट में एक ऐलान, फिर रॉकेट की तरह भागने लगे 10 शेयर

मुंबई। बजट वाले दिन शेयर बाजार (Stock Market) भले ही फ्लैट लेवल पर क्लोज हुआ हो, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में बजट पेश करने के दौरान क्लास के लिए इनकम टैक्स (Income Tax) में छूट का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया, तो इसके बाद कन्जंप्शन शेयर (Consumption Stocks) ने अचानक दौड़ लगा दी. जोमैटो से लेकर मारुति तक के शेयर उछल गए, तो वहीं टाटा कंज्यूमर और नेस्ले इंडिया के शेयर ने भी रफ्तार पकड़ ली।

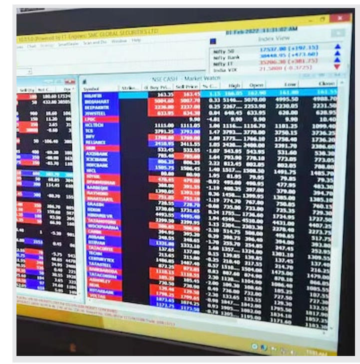

बजट वाले दिन बाजार में नजर आई सुस्ती

बजट का शेयर पर खास असर देखने को नहीं मिला और Sensex-Nifty ने दिनभर सुस्ती में कारोबार किया और अंत में फ्लैट लेवल पर क्लोज हुए. बीएसई सेंसेक्स 77,637 अंक पर खुला और कारोबार के अंत में 5.39 अंक की मामूली तेजी लेकर 77,506 पर बंद हुआ. वहीं दूसरी ओर निफ्टी 26.25 अंक फिसलकर 23,482.15 पर बंद हुआ।

क्यों भागे कन्जंप्शन वाले शेयर?

अब बताते हैं कि आखिर क्यों इन शेयरों में अचानक जोरदार तेजी आई, तो इसके पीछे कारण सरकार की ओर से मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स के दायरे को बढ़ाने का ऐलान ही है. दरअसल, एक्सपर्ट्स की मानें तो सरकार के इस ऐलान के बाद लोगों के पास खर्च करने के लिए नकदी बढ़ेगी और बाजार में पैसा आएगा. इससे तमाम सेक्टर्स में खपत बढ़ने की उम्मीद है और ऐसे में कंज्यूमर गुड्स की खपस पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

ये 10 शेयर खूब भागे

भले ही बाजार फ्लैट बंद हुआ, लेकिन कंज्यूमर और कन्जंप्शन बेस्ड शेयरों ने तगड़ी छलांग लगाई. अगर बात करें बजट वाले दिन सबसे ज्यादा भागने वाले स्टॉक्स के बारे में, तो Blue Star Corp (13.17%) की तेजी लेकर 2057.85 रुपये और Tata Consumer Share (10.41%) की तेजी लेकर 1,067.30 रुपये पर क्लोज हुआ. Zomato Share (7.17%) की उछाल के साथ 236.15 रुपये पर बंद हुआ.

बजट को लेकर असमंजस में दिखा बाजार

सेंसेक्स में मामूली बढ़त, निफ्टी लाल निशान पर बंद

मुंबई। आम बजट के दिन शनिवार को आयोजित विशेष कारोबारी सत्र में स्थानीय शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला और अंततः बाजार लगभग स्थिर रुख के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 5.39 अंक की मामूली बढ़त के साथ 77,505.96 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 26.25 अंक की गिरावट के साथ 23,482.15 अंक पर बंद हुआ। केंद्रीय बजट खुदरा निवेशकों और समग्र बाजार के लिए अधिक उत्साहजनक नहीं रहा। हालांकि, नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर-मुक्त करने और कर स्लैब में बदलाव से उपभोग से संबंधित क्षेत्रों में खरीदारी बढ़ी। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ₹बाजार ने बजट पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। पूंजीगत व्यय में महज 10% की वृद्धि बाजार की अपेक्षाओं से कम रही, जिससे रेलवे, रक्षा और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों पर असर पड़ा है। व्यापार के दौरान सेंसेक्स ने 77,899.05 अंक का उच्चतम और 77,006.47 अंक का न्यूनतम स्तर छुआ, जिसमें कुल 892.58 अंकों का उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। वहीं, निफ्टी ने 23,632.45 अंक के उच्च और 23,318.30 अंक के निचले स्तर को छुआ। इससे पहले के चार कारोबारी सत्रों में बाजार में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन बजट के बाद निवेशकों में असमंजस का माहौल नजर आया।

नजरें आगे के रुझानों पर

विशेषज्ञों के अनुसार, बाजार की दिशा अब बजट प्रावधानों के क्रियान्वयन, वैश्विक आर्थिक संकेतों और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर निर्भर करेगी। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे सतर्कता बरतें और दीर्घकालिक निवेश के फैसले सोच-समझकर लें।

खेल बजट में हुई बंपर बढ़ोतरी

खेलो इंडिया से खिलखिलाएगा भारत

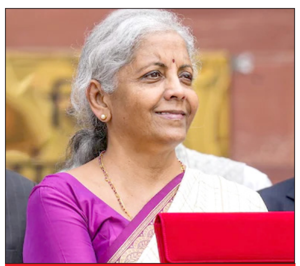

सरकार ने खोला खजाना

एजेंसी । नई दिल्ली

जमीनी स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज और उन्हें प्रोत्साहित करने की सरकार की प्रमुख योजना खेलो इंडिया से भारत खिलखिलाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेश केंद्रीय बजट में खेलो इंडिया के लिए फिर खजाना खोला। इस महत्वाकांक्षी योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह 2024-25 के 800 करोड़ के अनुदान से 200 करोड़ रुपये अधिक हैं। वहीं खेलों के लिए आवंटन में 351.98 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

- **200 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है खेलो इंडिया के बजट में, मिले एक हजार करोड़**
- **351 करोड़ 98 लाख की वृद्धि खेलों के कुल बजट में की गई है, कुल 3,794.30 करोड़ मिले**

'यह खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ खेलो इंडिया को बढ़ावा देगा और युवा-केंद्रित विकास पहलों का विस्तार करेगा। इससे खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी सशक्त होगी।'

–मनसुख मंडाविया, खेल मंत्री

3,794.30 करोड़ रुपये आवंटित

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय को कुल मिलाकर 3,794.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। यह रकम पिछले साल की तुलना में 351.98 करोड़ रुपये अधिक है। यह बढ़ोतरी इस बात को ध्यान में रखते हुए अधिक है कि अगले वर्ष ओलंपिक, राष्ट्रमंडल या एशियाई खेलों जैसा कोई बड़ा खेल आयोजन नहीं है। राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता के लिए निर्धारित राशि को भी 340 करोड़ रुपये से मामूली तौर पर बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है। भारत वर्तमान में 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए एक महत्वाकांक्षी बोली की तैयारी कर रहा है। भारत ने इसके लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति को एक आशय पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रोत्साहन अनुदान घटाया

सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए अनुदान को 42.65 करोड़ रुपये से घटाकर 37 करोड़ रुपये करने का फैसला किया है। इसी तरह की कटौती की घोषणा राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम और युवा छात्रावास के कोष में भी की गई है। बहुपक्षीय निकायों और युवा विनिमय कार्यक्रमों के लिए योगदान को हालांकि 11.70 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 55 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

यहां भी वृद्धि

- जम्मू-कश्मीर में खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए 20 करोड़ के कोष को मंजूरी दी गई है, जो पिछले साल से 14 करोड़ ज्यादा अधिक है
- राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को वित्तीय वर्ष में 23 करोड़ रुपये मिलेंगे जो 2024-25 के 18.70 करोड़ रुपये से ज्यादा हैं
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) का बजट 20.30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 24.30 करोड़ रुपये कर दिया गया

एनएसएस को 450 करोड़

बढ़े हुए बजट का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) को दिया जाएगा। इसे 450 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो पिछले वर्ष से 200 करोड़ रुपये अधिक है। राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य स्कूलों और कॉलेजों में युवाओं के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करना है। यह एक ऐसी योजना है जो सामाजिक कार्य और सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं को आकार देने की दिशा में काम करती है।

साई को अब मिलेंगे 830 करोड़

राष्ट्रीय शिविरों के संचालन और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए साजो-सामान व्यवस्था के लिए नोडल निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के लिए आवंटन 815 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 830 करोड़ कर दिया गया। साई देश भर में स्टेडियमों के रखरखाव और उपयोग के लिए भी जिम्मेदार है। साल 1998 में गठित राष्ट्रीय खेल विकास कोष में 18 करोड़ रुपये का योगदान लगातार दूसरे वर्ष जारी रहेगा।

सूर्य और संजू को दिखाना होगा दम

- इंग्लैंड के खिलाफ पांचवां और अंतिम मुकाबला आज
- पहले ही सीरीज पर कब्जा कर चुकी है भारतीय टीम

आमने-सामने

कुल मैच :	28
भारत जीता :	16
इंग्लैंड जीता :	12

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

पहले ही सीरीज मुट्ठी में कर चुकी टीम इंडिया रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ पांचवां और अंतिम टी-20 जीतकर शानदार अंत करना चाहेगी। इस मुकाबले में सभी की निगाह संजू सैमसन और कप्तान सूर्यकुमार यादव के प्रदर्शन पर रहेंगी। यह दोनों रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। संजू पिछले चार मुकाबलों में से सिर्फ एक में 20 का आंकड़ा छू पाए हैं और सिर्फ 35 रन बनाए हैं। वहीं सूर्यकुमार तो एक बार भी 15 भी क्रास नहीं कर सके। वह दो बार तो खाता भी नहीं खोल पाए हैं।

13 साल बाद वानखेड़े में टकराएंगे दोनों

दोनों टीमें 13 साल बाद वानखेड़े स्टेडियम में खेलेंगी। पिछली बार दिसंबर 2012 में खेले थे जिसमें धौनी की कप्तानी वाली टीम को इयोन मोर्गन की टीम ने छह विकेट से धोया था। मौजूदा कोच गौतम गंभीर उस टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 17 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने तीन मैच यहां खेले हैं जिसमें से दो जीते और एक हारा है। अंग्रेजों ने अपना पिछला मुकाबला 2016 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो विकेट से जीता था।

भारतीय टीम को कप्तान और सैमसन से बड़ी पारी की उम्मीद

सैमसन इस सीरीज से पहले केरल की तरफ से विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं खेले थे। उनके खेल में मैच अभ्यास की कमी स्पष्ट नजर आ रही है। वह मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर की तेज और उठती हुई गेंदों के सामने संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। टीम सलामी जोड़ी के अपने संयोजन में किसी तरह से बदलाव करेगा। अभिषेक शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। वह 197.26 की स्ट्राइक रेट से सीरीज में सर्वाधिक 144 रन बना चुके हैं। संजू इस मैच में बड़ी पारी खेलकर अभिषेक के साथ टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाना चाहेंगे। वहीं दुनिया के चौथे नंबर के बल्लेबाज सूर्यकुमार आठ महीने पहले बांग्लादेश के खिलाफ 75 रन बनाने के बाद कोई अच्छी पारी नहीं खेल पाए हैं। वह अपने घरेलू मैदान वानखेड़े पर बड़ी पारी खेल कर फॉर्म में वापसी करना चाहेंगे। पिछले मैच में नाकाम रहने के बाद तिलक वर्मा भी लय में लौटने को तेबात होंगे। चोट से वापसी करने के बाद रिंकू सिंह ने 30 रन की पारी खेलकर अपनी फॉर्म और फिटनेस को लेकर जताई जा रही चिंता को दूर कर दिया है। वह अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखना चाहेंगे। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे भी बल्लेबाजों के लिए मददगार पिच पर फिर से अपना जलवा दिखाना चाहेंगे। चोट से उबरकर वापसी करने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को तीसरे मैच में मौका दिया था पर चौथे मैच में विश्राम दिया गया। टीम प्रबंधन उन्हें अंतिम एकादश में शामिल करके उनकी फिटनेस का एक बार फिर से आकलन करना चाहेगा।

राणा के खेलने पर इंग्लैंड ने उठाए सवाल

इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने शुक्रवार को मैच के दौरान मध्यम गति से गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर शिवम दुबे के 'कनकशन सब' (किसी खिलाड़ी के सिर में गेंद लगने पर उसकी जगह लेने वाला स्थानापन्न खिलाड़ी) के रूप में विशेषज्ञ तेज गेंदबाज हर्षित राणा को लेने के भारत के फैसले पर नाराजगी जताते हुए इस बार सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी टीम से सलाह नहीं ली गई। वे मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ से यह स्पष्ट करने के लिए कहेंगे कि चोट लगने की स्थिति में समान योग्यता वाले खिलाड़ी को उतारने का वास्तव में क्या मतलब है।

15 साल के कार्तिक ने कट हासिल कर रचा इतिहास

गोल्फ

एजेंसी । गुरुग्राम

भारतीय अमेच्योर गोल्फ खिलाड़ी कार्तिक सिंह शनिवार को यहां 'इंटरनेशनल सीरीज इंडिया में कट हासिल कर एशियाई टूर स्पर्धा में यह उपलिब्ध हासिल करने वाले उपमहाद्वीप के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। 15 साल के कार्तिक ने डीएलएफ गोल्फ और कंट्री क्लब में दूसरे दौर में एक अंडर 71 का कार्ड खेला जिससे उनका कुल स्कोर चार ओवर हो गया। कट स्कोर आठ अंडर था। भारत के कुल 10 खिलाड़ी कट हासिल करने में सफल रहे जिसमें सिर्फ लाहिड़ी का स्कोर अंडर (एक अंडर) है।

कोहली की मौजूदगी में दिल्ली ने दिखाई दिलेरी

- **लवे को तीसरे ही दिन पारी और 19 रन से हराया**

रणजी ट्रॉफी

एजेंसी । नई दिल्ली

दिल्ली का चिकू यानी किंग कोहली भले ही रणजी में 15 गेंदों में सिर्फ छह रन बना पाया पर उनका जादू मैदान के अंदर और बाहर खूब चला। उनकी मौजूदगी में दिल्ली टीम के यवुाओं ने दिलेरी देखते हुए

रेलवे को तीसरे ही दिन शनिवार को पारी और 19 रन से धोकर सत्र की दूसरी जीत दर्ज कर मैच को यादगार बना दिया। हालांकि दूसरी पारी में कोहली को बल्लेबाजी करते हुए देखने के लिए अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे दर्शकों को निराश होकर लौटना पड़ा।

अच्छी-खासी भीड़ जुटी

कोहली को खेलते हुए देखने के लिए शुरुआती दो दिन अच्छी-खासी भीड़ जुटी थी पर तीसरे दिन सिर्फ दो से तीन हजार के करीब दर्शक ही पहुंचे थे। तेज गेंदबाज हिमांशु सांगवान ने शुक्रवार को ऑफ स्टंप उखाड़कर उनका बेशकीमती विकेट लिया। कोहली ने 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी की। उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम में काफी समय बिताया, हाथ मिलाया और तस्वीरें खिंचवाईं।

गुजरात ने कटाया क्वार्टर फाइनल का टिकट

एजेंसी । अहमदाबाद

आर्या देसाई और जयमीत पटेल के अर्धशतकों और स्पिनर देसाई की फिरकी से गुजरात ने शनिवार को इलीट ग्रुप बी मैच में हिमाचल प्रदेश को नौ विकेट से हराकर क्वार्टर फाइनल में स्थान पक्का किया। देसाई ने चार जबकि उनके स्पिन जोड़ीदार विशाल जायसवाल ने तीन विकेट झटके। इससे गुजरात ने हिमाचल प्रदेश को 62.5 ओवर में 175 रन पर समेट दिया। इससे गुजरात को 144 रन का लक्ष्य मिला। सलामी बल्लेबाज उर्विल पटेल (25) के जल्दी आउट होने के बाद आर्या (57 गेंद, 59 रन, पांच चौके, छह छक्के) और जयमीत (68 गेंद, 51 रन, छह चौके) ने नाबाद 114 रन की साझेदारी बनाई जिससे गुजरात ने 22.3 ओवर में जीत दर्ज की।

आंध्र ने राजस्थान को हराया

विजयनगरम। त्रिपुराना विजय और रिकी भुई के शानदार प्रदर्शन से आंध्र ने रणजी मैच के तीसरे दिन राजस्थान को छह विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने सुबह सात विकेट पर 95 रन से खेलते हुए दूसरी पारी में महज 19 रन जोड़े और उसकी पारी 114 रन पर सिमट गई। विजय ने पांच विकेट झटके जिससे आंध्र को 152 रन का लक्ष्य मिला। भुई ने फिर 76 गेंद में 62 रन बनाए जबकि केएस भरत ने 59 गेंद में 43 रन की पारी खेली।

मुंबई के मैदानों से

इंडियन डर्बी : सैन्टीसिमो और सॉयकिक स्टॉर आमने-सामने

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

रविवार शाम पांच बजकर पैंतालीस मिनट पर महालक्ष्मी रेसकोर्स के हरे-भरे ट्रैक पर दुधिया रोशनी में देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित घुड़दौड़ एचपीएसएल इंडियन डर्बी में अपना बर्चस्व स्थापित करने के लिए पेसी श्रॉफ द्वारा प्रशिक्षित सैन्टीसिमो और सॉयकिक स्टॉर एक दूसरे के आमने-सामने होंगे। वैसे दौड़ में सोलह घोड़े हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला इन दोनों के बीच नजर आ रहा है। इंडियन डर्बी में हमेशा ही छुपे रुस्तम घोड़ों का अपना महत्व रहा है, इस बार भी दौड़ में कास्टील, ड्युक ऑफ टस्कॉनी और गोल्डन थंडर अंत में छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं। कुल नौ दौड़ों का कार्यक्रम रखा गया है। पहली दौड़ 2.15 बजे आरंभ होगी। विभिन्न् दौड़ों के लिए हमारे चयन इस प्रकार हैः 1- कॉन्स्टेबल (प्र.), टाईमलेस विजन (द्वि.), 2- किंग्स गैम्बिट (प्र.), वॉरलाक (द्वि.), 3- वन्स यू गो ब्लैक (प्र.), क्रिस्टोफल (द्वि.), 4- ओलिवर (प्र.), श्योरियलिस्ट (द्वि.), 5- ज़कारो (प्र.), इवाल्डो (द्वि.), 6- गियाकोमो (प्र.), मिरॉकल स्टॉर (द्वि.), 7- सैन्टीसिमो (प्र.), सॉयकिक स्टॉर (द्वि.), 8- चार्डीकला (प्र.), रेड मिस्ट (द्वि.), 9- एला चोले (प्र.), बेट्सी (द्वि.), दिन का सर्वोत्तम- ओलिवर।

शेफाली शाह फिर OTT पर जमाएंगी धाक

OTT पर फरवरी में एक से बढ़कर एक वेब सीरीज दर्शकों का मनोरंजन करने आ रह हैं। इन्हीं में से एक 'दिल्ली क्राइम' का तीसरा सीजन भी है, जिसका इंतजार दर्शक पिछले काफी समय से बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं।

DCP वर्तिका चतुर्वेदी यानी शेफाली शाह फिर से OTT पर आ रही हैं 'दिल्ली क्राइम' का सीजन 3 लेकर। उन्होंने सोशल मीडिया पर तीसरे सीजन की रिलीज तारीख का ऐलान कर दिया है। शेफाली ने अपना एक पोस्टर साझा किया और लिखा, 'लाइट्स, कैमरा, टुडम - जो आने वाला है उसके लिए आप तैयार नहीं हैं। जानिए 3 फरवरी, 2025 को नेटफ्लिक्स पर क्या आ रहा है, जी हां दिल्ली क्राइम सीजन 3'। बता दें कि पहले 2 सीजन की तरह ही इस बार भी DCP वर्तिका यानी शेफाली 'दिल्ली क्राइम में अपराध की गुत्थियां सुलझाती दिखेंगी। तीसरे भाग में हुमा कुरैशी की एंट्री भी हुई है।

'नादानियां' करेंगे इब्राहिम अली खान

पिछले काफी समय से सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान की पहली फिल्म को लेकर चर्चा हो रही है। उनके पहले प्रोजेक्ट से जुड़ी तमाम जानकारियां सामने आईं, लेकिन इसका आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ था। अब आखिरकार 'नादानियां' से इब्राहिम और फिल्म में उनकी जोड़ीदार खुशी कपूर की पहली झलक दर्शकों के बीच आ गई है। पोस्टर सामने आते ही इब्राहिम के प्रशंसकों का उत्साह दोगुना हो गया है।

नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी फिल्म

धर्मा प्रोडक्शंस ने फिल्म का पोस्टर साझा कर सोशल मीडिया पर लिखा, 'हर प्रेम कहानी में थोड़ी सी नादानी होती है। इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर को मुख्य किरदार में लॉन्च किया गया। देखिए 'नादानियां'। जल्द आ रही है केवल नेटफ्लिक्स पर।' फिल्म में इब्राहिम ने नोएडा के मध्यमवर्गीय परिवार के एक मेहनती लड़के का किरदार निभाया है, वहीं खुशी इसमें दिल्ली की हिम्मती लड़की पिया की भूमिका में होंगी। शाउना गौतम ने इस फिल्म का निर्देशन किया है।

फिल्म की कहानी

बता दें कि यह फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी है। 'नादानियां' एक रोमांटिक ड्रामा है, जो युवाओं की जिंदगी को दिखाती है, खासकर उनके पहले प्यार के अनुभव को। फिल्म की कहानी पिया नाम की एक लड़की और अर्जुन नाम के लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों की पूरी तरह से अलग दुनिया है, लेकिन जब ये मिलते हैं तो उनका सफर प्यार, शरारत और मासूमियत से भरा होता है।

प्रतीक बब्बर कर रहे दूसरी शादी

अभिनेता प्रतीक बब्बर अपनी पेशेवर जिंदगी के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब चर्चा में रहे हैं। एक ओर जहां सान्या सागर के साथ उनकी शादी और तलाक ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं, वहीं पिछले कुछ समय से प्रिया बनर्जी के साथ उनका रिश्ता चर्चा का विषय बना हुआ है। अब खबर है कि दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। उन्होंने साल 2023 में वैलेंटाइन डे के मौके पर अपना यह रिश्ता सार्वजनिक किया था। दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे प्रतीक तलाक के 2 साल बाद फिर से शादी करने जा रहे हैं।

प्रतीक के घर पर होगी शादी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह शादी प्रतीक के मुंबई के बांद्रा स्थित घर पर होगी। हालांकि, दोनों ने इस शादी की पुष्टि नहीं की है। कहा जा रहा है कि यह एक बेहद निजी समारोह होगा। प्रतीक और पूजा के परिवारवाले और करीबी दोस्त ही उनकी इस शादी में शामिल होंगे। प्रतीक पिछली बार फिल्म 'ख्वाबों का झमेला' में नजर आए थे, जबकि ईद के मौके पर वह सलमान खान के साथ फिल्म 'सिंकदर' में दिखेंगे। प्रिया साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री हैं। प्रतीक से उनकी पहली मुलाकात टीवी इंडस्ट्री के एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी।

DBD दो बजे दोपहर
पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है
मुंबई, रविवार, 2 फरवरी 2025

राज्यों को 25,01,284 करोड़ रुपये मिलेंगे

कुल राजस्व प्राप्ति 34,20,409 करोड़ रुपये

रक्षा बजट

बजट में रक्षा मंत्रालय को मिले 6.8 लाख करोड़

आर्मी मॉर्डनाइजेशन नए हथियारों की खरीद और रिसर्च पर निवेश

एजेंसी । नई दिल्ली

बजट 2025 में रक्षा क्षेत्र के लिए भी बड़ा आवंटन किया गया है। केंद्रीय बजट 2025 में भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए 6.8 लाख करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया गया है।

बजट में डिफेंस सेक्टर को क्या मिला?

केंद्रीय बजट 2025 में रक्षा यानी डिफेंस क्षेत्र के लिए कुल 6.8 लाख करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया गया है। जानकारी के मुताबिक, ये बजट अनुमानित जीडीपी का 1.91 प्रतिशत है। 6.8 लाख करोड़ रुपये के रक्षा बजट में 1.8 लाख करोड़ रुपये कैपिटल बजट के लिए रखा गया है। बता दें कि इस रकम से नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजोसामान खरीदे जाएंगे।

यहां समझें बजट का बंटवारा

केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय के लिए रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। इसमें 9.53% की वृद्धि हुई है। सशस्त्र बलों के पूंजीगत बजट के तहत 1.80 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट में सेना का आधुनिकीकरण एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है। घरेलू उद्योगों से खरीद के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। रक्षा पेंशन के लिए आवंटन में 14% की वृद्धि की गई है। ECHS के लिए 8,317 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट में 12% की बढ़ोतरी की गई है। ICG के कैपिटल बजट में 43% की महत्वपूर्ण बढ़त हुई है। कैपिटल हेड के तहत बीआरओ को 7,146 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय

देश के बॉर्डर व नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी होगी मजबूत

2,87,333.16 करोड़ रुपये आवंटित

एजेंसी । नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय का आवंटन बढ़ाकर 2.87 लाख करोड़ रुपये किया है। इस बजट से देश के सीमा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दो लेन व चार लेन राष्ट्रीय राजमार्गो का जाल बिछाने पर फोकस रहेगा। इसके अलावा, बजट में पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों व जिलों की रणनीतिक महत्वपूर्ण रोड कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2,87,333.16 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह राशि इससे पिछले वित्त वर्ष के 2,80,518.80 करोड़ रुपये के परिव्यय से 2.41 प्रतिशत अधिक है। निर्मला सीतारमण ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के लिए आवंटन भी सालाना आधार पर 1,693,71 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,878,03 करोड़ रुपये कर दिया। इस धन से देशभर में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, नए एक्सेस कंट्रोल राजमार्ग, एक्सप्रेस-वे व भारतमाला के अंतगर्त परियोजनाओं को रफ्तार दी जाएगी।

खास बातें...

- पहाड़ी राज्यों में रोपवे परियोजनाओं पर 300 करोड रुपये खर्च होंगे
- आदिवासी क्षेत्रों में दो लेन व चार लेन राष्ट्रीय राजमार्गो की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी
- अरुणाचल प्रदेश में फ्रंटियर हाइवे परियोजना को रफ्तार दी जाएगी
- राज्य राजमार्गो को विकसित करने में 10,383 करोड रुपये खर्च किए जाएंगे
- मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पर 400 करोड रुपये निवेश किए जाएंगे

सड़क दुर्घटना में घायलों का कैशलेस इलाज

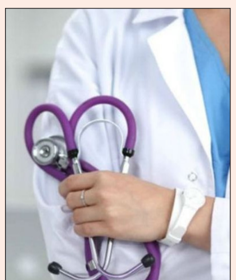

बजट में सड़क दुर्घटना में घायलों को कैशलेस इलाज योजना को लागू करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत मोटर वाहन अधिनियम 1988 के सेक्शन 162 के तहत कानूनी जामा पहनाया जाएगा। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूर्व में घोषित नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड के गठन की फिर से घोषणा की गई है। यह बोर्ड सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शोध व सड़क हादसों की जांच के लिए थर्ड पार्टी की भूमिका निभाएगा। बोर्ड के एक अध्यक्ष व विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवार बतौर सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

रेल बजट

2.55 लाख करोड़ रुपये आवंटित

एजेंसी । नई दिल्ली

भारतीय रेल देश की जीवनरेखा है। बजट में रेलवे के लिए बड़े एलान होने की उम्मीद थी, लेकिन इस बार सरकार ने रेलवे के बजट में कोई खास बड़े एलान करने से परहेज किया है। केंद्रीय बजट में रेलवे मंत्रालय के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें राजस्व में 3445 करोड़ रुपये और कैपिटल एक्सपेंडिचर में 2,52,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस तरह रेलवे बजट में कुल 2,55,445 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बजट में पेंशन फंड में 66 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं। नई लाइनें बिछाने के लिए 32,235 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। लाइनों के दोहरीकरण में 32,000 करोड़ और गॉज लाइन में बदलने में 4,550 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।

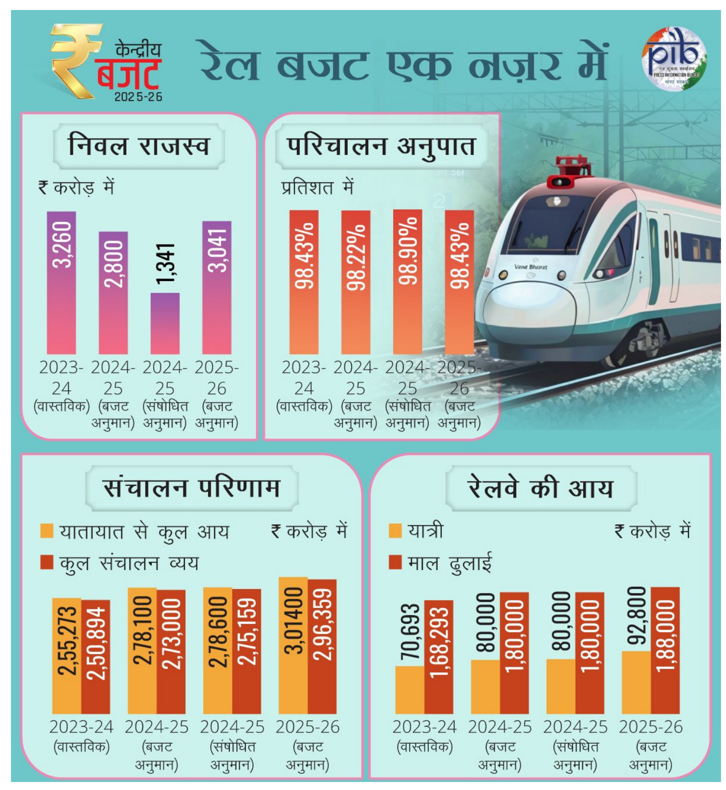

सुरक्षा पर विशेष ध्यान

- 64,235 करोड़ से रेल लाइनों का दोहरीकरण व नए रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे
- 22,800 करोड़ रुपये मौजूदा रेलवे ट्रैक के नवीनीकरण पर खर्च होंगे
- 7000 करोड़ रुपये की लागत से रोड ओवर ब्रिज व रोड अंडर ब्रिज बनाए जांएगे 57950 करोड़ रुपये खर्च होंगे टक्करोधी तकनीक कवच, सिग्नल सिस्टम अपग्रेड करने पर

सुरक्षित रेलवे ट्रैक पर दौडेंगी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में रेलवे के ट्रैक को अधिक सुरिक्षत बनाने और उन पर सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन के परिचालन को अहमियत दी है। बजट में रेल रेल मंत्रालय को 3,02,100 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है। इनमें से 2,55,000 करोड़ रुपये नई पटरियों, पटरियों के दोहरीकरण के अलावा वंदे भारत, वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत ट्रेन के कोच निर्माण पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं व खानपान को बेहतर बनाने के उपाय किए जाएंगे। बजट में रेलवे के बुनियादी ढांचे को आधुनिक व विश्व स्तरीय बनाने पर जोर रहेगा। सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में रेलवे को 2,79,000 रुपये का आवंटन किया था। आम बजट 2025-26 में 23,100 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। तीन लाख करोड़ से अधिक के बजट में रेलवे के बुनियादी ढांचे को आधुनिक व विश्व स्तरीय बनाने पर जोर रहेगा।

आरामदायक होगा सफर

- 64,224 करोड़ रुपयों से सेमी हाई स्पीड ट्रेन-वंदे भारत, वंदे भारत स्लीपर, अमृत भारत, वंदे मेट्रो ट्रेन के कोच बनेंगे
- 9343 कोच उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है इस बार
- 12,118 करोड रुपये खानपान सेवा, स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं पर खर्च होंगे

स्वास्थ्य क्षेत्र को मिली नई संजीवनी

- 36 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती सभी जिला अस्पतालों में
- कैंसर डे केयर सेंटर बनेंगे
- गिग वर्कर्स को मेडिक्लेम

एजेंसी । नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी (शनिवार) को 2025-2026 का बजट पेश किया। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 98,311 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह पिछले साल के 89,287 करोड़ रुपये के मुकाबले 9.8% ज्यादा है। इस बार सरकार ने कैंसर इलाज, मेडिकल कॉलेज, जीवनरक्षक दवाओं और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया है।

200 कैंसर डे-केयर सेंटर खोले जाएंगे

इस बार सरकार 200 नए कैंसर डे-केयर सेंटर खोलने जा रही है, जिससे मरीजों को उसी दिन इलाज मिल सके और वे जल्द घर लौट सकें। इन सेंटरों में कीमोथेरेपी, परामर्श, मेडिकल सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी।

36 जीवनरक्षक दवाएं सस्ती होंगी

36 ज़रूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाएँ सस्ती हो जाएंगी। 6 अन्य दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% तक घटाई गई है। 37 अन्य दवाएँ और 13 मरीज सहायता योजनाएँ भी टैक्स छूट में शामिल की गई हैं।

- कैंसर समेत गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल 36 दवाएं सस्ती होंगी।
- 6 जरूरी जीवन रक्षक दवाओं के आयात पर केवल 5% कस्टम ड्यूटी लगेगी।
- हर जिले के सरकारी अस्पताल में कैंसर डे केयर सेंटर खुलेंगे। 200 सेंटर इसी साल खुलेंगे।
- मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में अगले साल 10 हजार और 5 साल में 75 हजार सीटें जुड़ेंगी।
- वीजा नियमों में बदलाव कर देश में मेडिकल टूरिज्म और 'हील इन इंडिया' स्कीम शुरू होगी।
- गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी ब्वॉयज जैसे काम कर रहे युवाओं को जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा।
- सभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी।

मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा

रहील इन इंडियार स्कीम के तहत भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की योजना बनाई गई है। विदेश से मरीजों को भारत लाने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। इससे रोजगार बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा का फायदा मिलेगा।

जिला अस्पतालों में कैंसर डे-केयर सुविधा

अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में कैंसर डे-केयर सेंटर खोले जाएंगे। यहां कैंसर मरीजों को जल्द इलाज और मानसिक सहयोग मिलेगा।

बजट पर विपक्ष

बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। आगामी बिहार चुनावों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। पिछली बार भी सभी घोषणाएं आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए की गई थीं। आंध्र प्रदेश के चुनाव खत्म हो चुके हैं और बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए राज्य फोकस में है। पश्चिम बंगाल को पिछले दस वर्षों में कुछ नहीं मिला और न ही आज कुछ मिला।

- अभिषेक बनर्जी, राष्ट्रीय महासचिव तृणमूल कांग्रेस

यह देश के लिए, खासतौर पर मध्यम वर्ग के लिए, एक बड़ी निराशा है। वित्त मंत्री का दावा है कि वे 12 लाख रुपये तक की कर छूट दे रही हैं, लेकिन अगली ही पंक्ति में वह कहती हैं कि 8 से 10 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत कर स्लैब है। चूंकि बिहार में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए बिहार के लिए कई घोषणाएं की जा रही हैं, जिससे बिहार की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है।

- दयानिधि मारन, द्रमुक नेता एवं लोकसभा सदस्य

इस बजट से छोटे व्यापारियों को क्या फायदा मिल रहा है, आपने उनकी 12 लाख रुपये की आय पर कोई कर राहत नहीं दी है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी कि अगर आप तय कर लें कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ नहीं करेंगे, अपने पूंजीपति मंत्रियों का कर्ज माफ नहीं करेंगे और अब तक माफ किए गए 16 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को वसूल कर लें तो देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें और आयकर की दरें आधी हो सकती हैं।

- संजय सिंह, आम आदमी पार्टी (आप) सांसद

केंद्र ने न तो किसानों को उनकी फसलों पर एमएसपी दी है और न ही राज्य को किसी उद्योग के लिए कोई पैकेज दिया है। पंजाब को ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और भविष्य में सुधार हो सके। यह बजट चुनावी बजट है, जिसमें केवल बिहार राज्य के लिए घोषणाएं हैं। एक बार फिर केंद्र ने बजट में पंजाब और पंजाबियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है।

- भगवंत मान, मुख्यमंत्री पंजाब

पक्षपातपूर्ण है केंद्रीय बजट

तमिलनाडु को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। कई मांगें रखने के बावजूद, केंद्र के पास कम से कम एक मांग की पुष्टि करने और बजट में इसकी घोषणा करने का दिल नहीं है। बजट में तमिलनाडु का नाम तक नहीं लिया गया।

- एमके स्टालिन, मुख्यमंत्री, तमिलनाडु